सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 162, नई दिल्ली । गुरुवार, 22 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

तुम्हारी आवाज ही तुम्हारा हथियार है, अपने पौरुष को जगाओ और इस आजादी का जश्न मनाओ

03 भारत बंद के कॉल का असर दिल्ली में रहा बेअसर

06 शिक्षा जगत के लिए चुनौतियां

08 एक राज्यसभा आसन के लिए दो बीजेपी नेता अपना नामांकन पत्र दाखिल किया

दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी द्वारा एक और तकनीकी अधिकारी को नियुक्त किया गया गैर तकनीकी पद पर

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत तकनीकी अधिकारी को गैर तकनीकी पद पर आसीन करने की प्रक्रिया तेजी पर है। आज फिर एक तकनीकी अधिकारी को गैर तकनीकी पद आसीन कर दिया गया और उस पद पर आसीन गैर तकनीकी अधिकारी को तकनीकी पद पर आसीन कर दिया। *हमनें कल ही आपकों अवगत करवाया था कि दिल्ली परिवहन विभाग में आला अधिकारी दिल्ली प्रशासक की मूक सहमति प्राप्त कर परिवहन विभाग से तकनीकी अधिकारियों को तकनीकी पदो से हटा कर गैर तकनीकी पदो पर आसिन कर रहे हैं और गैर तकनीकी अधिकारियों को तकनीकी पदो पर जिससे परेशान होकर विभाग में बचे हुए तकनीकी अधिकारी वीआरएस लेकर विभाग से बाहर हो जाए और दिल्ली परिवहन विभाग पूर्ण रूप से तकनीकी से गैर तकनीकी हो जाए। *दिल्ली की

जनता के भविष्य और जान माल की असुरक्षा से इन्हे कुछ लेना देना नहीं है और ना ही दिल्ली की जनता की सुरक्षा की इन्हे कोई परवाह है, और यह सभी कुछ जानते हुए भी दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भारत सज्ञान नही ले रहा, बड़ा सवाल ? अपनी और अपनी बहन बेटियों की सार्वजानिक सवारी सेवा और सड़को पर सुरक्षा हेतु अब दिल्ली की जनता को स्वयं जागरूक होना होगा ।

जन हित में सूचना

संजय बाटला

दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना जनता को पूर्व सूचना दिए फिर से एक बार दिल्ली ईस्ट के अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को विलय करने के आदेश पारित कर दिए हैं। परिवहन विभाग के आदेश के अनुसार लोनी और सूरजमल विहार क्षेत्रीय कार्यालय अब मयूर विहार क्षेत्रीय कार्यालय में विलय किए जा रहे है और इन दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों में ताला लगा दिया जाएगा और इन क्षेत्रों की जनता अब अपने परिवहन के कार्य के लिए मयूर विहार क्षेत्रीय कार्यालय में सम्पर्क करेंगे।

परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश की हिंदी रूपांतरण की हुई कापी आपके लिए इसी लेख में उपल्ब्ध है।

आपकी जानकारी हेतु बता दें परिवहन विभाग के आला अधिकारी की दृष्टि में दिल्ली की जनता को अब परिवहन विभाग कार्यालयों में कोई कार्य नहीं पड़ता हैं इसलिए पहले तीन क्षेत्रीय कार्यालय में ताला लगा दिया था और अब दो और कार्यालयों में ताला लगा दिया और जल्द ही दो और क्षेत्रीय कार्यालयों में ताले लगने के आदेश पारित हो सकते हैं और इसी प्रकार दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी के तानाशाही रवैए पर दिल्ली की जनता चुप बैठी रही तो कुछ ही समय में दिल्ली में सभी क्षेत्रीय कार्यालय बंद नजर आयेंगे और जनता फिर ढूढती रहेगी अपने रुके कार्यों को करवाने के लिए आला अधिकारी को।

सरकारी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली परिवहन विभाग (प्रशासन शाखा) 5/9 अंडर हिल रोड दिल्ली 110054

सीडी नंबर 075779310/466,20

आदेशः- दिनांकः 20 अगस्त 2024

विषयः क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लोनी रोड, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय सूरजमल विहार और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय मयूर विहार का मयूर विहार में एक संयुक्त इकाई में विलय

परिचालन दक्षता बढ़ाने, संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के हित में, मयूर विहार, सूरजमल विहार और लोनी रोड स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (जेडटीओएस) को एक एकल, संयुक्त इकाई में विलय करने का निर्णय लिया गया है। मयूर विहार स्थान.

सूरजमल विहार और लोनी रोड जोनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में वर्तमान में किए जा रहे सभी प्रशासनिक, परिचालन और सार्वजनिक-सामना वाले कार्यों को 27.08.2024 से मयूर विहार जोनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

डीटीओ (मयूर विहार) विलय की गई इकाई को संभालेंगे। सभी कर्मचारियों/कंप्यूटरों और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड (रिकॉर्ड रूम के अलावा) को 24 अगस्त 2024 और 26 अगस्त 2024 के बीच मयूर विहार कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाए।

तीन स्थानों पर ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक संबंधित एमवीआई/फोरमैन के अधीन काम करना जारी रखेगा, जो डी'टीओ मयूर विहार को रिपोर्ट करेगा। **लोनी रोड सूरजमल विहार स्थित डीटीओ कार्यालय को एक गार्ड की निगरानी में बंद कर दिया जाएगा और एक स्पष्ट बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें लिखा होगा कि कार्यालय के काम के लिए आवेदक निम्नलिखित पते पर डीटीओ मयूर विहार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं: मयूर विहार प्राधिकरण, प्रताप नगर, मयूर विहार, नई दिल्ली, दिल्ली, 110091।**

यह प्रमुख सचिव/ आयुक्त परिवहन जीएनसीटीडी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

रमन कुंग्स प्रशासनिक अधिकारी (परिवहन)

में कॉपीः -

1.प्रमुख सचिव सह आयुक्त परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी के पीए

2.सभी विशेष आयुक्त परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी के पीए

3.श्री. सिस्टम विश्लेषक, कंप्यूटर शाखा, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

रंजन कुमार प्रशासनिक अधिकारी (परिवहन)

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा कोर्ट को दिखाने के लिए जारी किया आदेश जिसको स्वयं पूरा नहीं करना चाहतीं, जानें

आदरणीय सुप्रीम कोर्ट मे आदेश के बाद परिवहन विभाग के तरफ़ यह नोटिफिकेशन लगभग एक साल पहले जारी किया गया यह नोटिफिकेशन "आदेशनुसार अगर किसी भी प्राइवेट नंबर प्लेट से कमर्शियल एक्टिविटी (सवारी उठाने का कार्य) की जाती है तो यह एक दंडनीय अपराध है।"

जिसके अंतर्गत प्रथम बार 5000, दूसरी बार 10000+ एक साल कारावास की प्रावधान है तथा इसको संचालित करने वाली प्राइवेट एप कंपनियों के ऊपर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है।

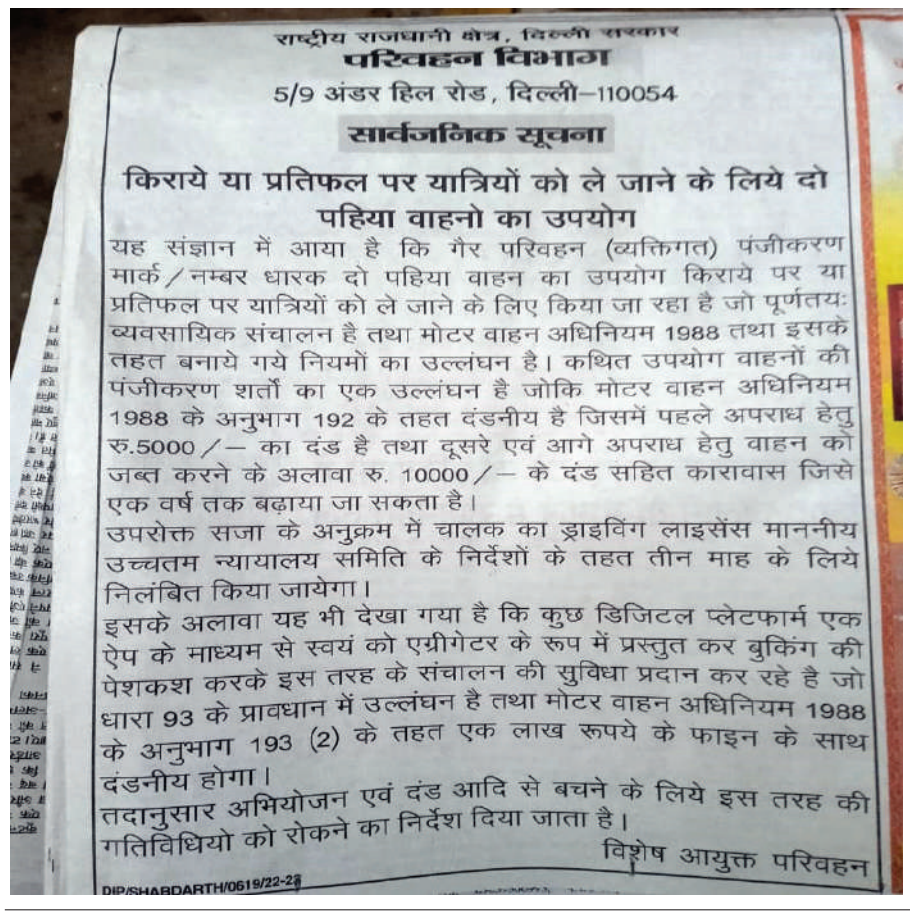

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
परिवहन विभाग
5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली–110054

सार्वजनिक सूचना

किराये या प्रतिफल पर यात्रियों को ले जाने के लिये दो पहिया वाहनो का उपयोग

यह संज्ञान में आया है कि गैर परिवहन (व्यक्तिगत) पंजीकरण मार्क/नम्बर धारक दो पहिया वाहन का उपयोग किराये पर या प्रतिफल पर यात्रियों को ले जाने के लिए किया जा रहा है जो पूर्णतयः व्यवसायिक संचालन है तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा इसके तहत बनाये गये नियमों का उल्लंघन है। कथित उपयोग वाहनों की पंजीकरण शर्तों का एक उल्लंघन है जोकि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुभाग 192 के तहत दंडनीय है जिसमें पहले अपराध हेतु रु.5000/— का दंड है तथा दूसरे एवं आगे अपराध हेतु वाहन को जब्त करने के अलावा रु. 10000/— के दंड सहित कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

उपरोक्त सजा के अनुक्रम में चालक का ड्राइविंग लाइसेंस माननीय उच्चतम न्यायालय समिति के निर्देशों के तहत तीन माह के लिये निलंबित किया जायेगा।

इसके अलावा यह भी देखा गया है कि कुछ डिजिटल प्लेटफार्म एक ऐप के माध्यम से स्वयं को एग्रीगेटर के रूप में प्रस्तुत कर बुकिंग की पेशकश करके इस तरह के संचालन की सुविधा प्रदान कर रहे है जो धारा 93 के प्रावधान में उल्लंघन है तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुभाग 193 (2) के तहत एक लाख रूपये के फाइन के साथ दंडनीय होगा।

तदानुसार अभियोजन एवं दंड आदि से बचने के लिये इस तरह की गतिविधियो को रोकने का निर्देश दिया जाता है।

विशेष आयुक्त परिवहन

DIP/SHABDARTH/0619/22-23

पुलिस ने एक मुफ्त यात्रा योजना शुरू की है

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। जहां कोई भी महिला जो अकेली है और उसे रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच घर जाने के लिए वाहन नहीं मिल रहा हो, वह पुलिस हेल्पलाइन नंबर (1091 और 7837018555) पर संपर्क कर सकती है और वाहन का अनुरोध कर सकती है। वे 24x7 घंटे काम करेंगे. कंट्रोल रूम का वाहन या नजदीकी पीसीआर वाहन/एसएचओ वाहन उसे सुरक्षित उसके गंतव्य तक पहुंचाएगा. यह निःशुल्क किया जाएगा। इस संदेश को अपने जानने वाले सभी लोगों तक पहुंचाएं। अपनी पत्नी, बेटियों, बहनों, माताओं, दोस्तों और उन सभी महिलाओं को नंबर भेजें जिन्हें आप जानते हैं .. उन्हें इसे सहेजने के लिए कहें .. सभी पुरुष कृपया उन सभी महिलाओं के साथ साझा करें जिन्हें आप जानते हैं। आपातकालीन स्थिति में महिलाएं **खाली संदेश या मिस्ड कॉल** कर सकती हैं .. ताकि पुलिस आपका स्थान ढूंढ सके और आपकी मदद कर सके । **पूरे भारत में लागू**

राष्ट्रहित | उद्योगहित | मजदूरहित

सरकार द्वारा डीटीसी की नयी बसें नहीं खरीदने तथा कर्मचारियों के स्थानान्तरण में बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में दिनांक 28/08/2024 को प्रातः 11:00 बजे डीटीसी मुख्यालय पर विशाल धरना/प्रदर्शन।

धरने को सफल बनाने हेतु **चलो डीटीसी मुख्यालय**

प्रमुख मांगें :-

- अन्य राज्य परिवहन निगमों की भांति डीटीसी के अपने बेड़े में बसों को खरीदा जाय।
- सभी अनुबन्धित चालकों/संवाहकों को स्थाई करने के लिए योजना बनाई जाय तथा स्थाई होने तक स्थाई चालको/संवाहकों की भांति मूल वेतन के बराबर वेतन दिया जाय।
- बसों के स्क्रैप होने तथा फेमा-II योजना के तहत बसों के संचालन हेतु कर्मचारियों के स्थानान्तरण बड़े स्तर पर किये जा रहे हैं। कार्मिक अनुभाग में कोई स्थानान्तरण योजना न होने के कारण कर्मचारियों के आवास से काफी दूर स्थानान्तरण किये जा रहे हैं जिससे कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है। इसके लिए स्थानान्तरण योजना बनाकर कर्मचारियों के आवास वाले क्षेत्रीय डिपों में ही स्थानान्तरण किये जाय।
- अनुकम्पा के आधार पर भर्ती संवाहकों को स्थाई किया जाय। पार्ट टाईम सफाई कर्मचारियों को फुल टाईम किया जाय तथा विकलांग संवाहकों का उत्पीड़न बन्द किया जाय।
- सभी सेवारत/सेवानिवृत कर्मचारियों पर कैशलेस मेडिकल योजना लागू की जाय।
- दि. परि. मजदूर संघ को मुख्यालय में शीघ्र कार्यालय दिया जाय।
- सभी श्रेणी के स्थाई कर्मचारियों को वार्षिक 30 ई.एल. का लाभ दिया जाय।

अपील :-

साथियों उपरोक्त सभी मांगो पर अपने समर्थन के लिए दिनांक 28/08/2024 को प्रातः 11:00 बजे हजारों की संख्या में पहुँचे डीटीसी मुख्यालय (आई.पी. स्टेट)

निवेदकः-

अध्यक्ष — श्री कैलाशचन्द मलिक
कार्य अध्यक्ष — श्री विनोद कुमार मलिक
महामन्त्री — श्री विजेन्दू सिंहमार

दिल्ली परिवहन मजदूर संघ
सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ(दिल्ली प्रदेश) एवं भा. परि. मजदूर महासंघ(नागपुर)
5239 अजमेरी गेट

पर्यावरण पाठशाला : जलजमाव - इसके दुष्प्रभाव और त्वरित सफाई की आवश्यकता : डॉ. अंकुर शरण

जलजमाव एक गंभीर समस्या है, जो न केवल हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कई खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकती है। बारिश या अन्य कारणों से पानी का जमा हो जाना और उसका समय पर निकास न होना, एक आम समस्या बन चुकी है। इस समस्या के चलते अनेक प्रकार के संक्रमण और बीमारियाँ फैल सकती हैं, जिनमें डेंगू, मलेरिया, और चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ प्रमुख हैं।

जलजमाव के कारण मच्छरों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है, जो इन बीमारियों को फैलाने के मुख्य वाहक होते हैं। इसके अलावा, जलजमाव से बदबू और गंदगी फैलती है, जिससे आसपास के लोगों के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है।

जलजमाव के दुष्प्रभावों को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे क्षेत्रों की तुरंत सफाई की जाए। पानी के निकास की उचित व्यवस्था करना, नियमित रूप से इन क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाना, और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ आम नागरिकों को भी इस समस्या के समाधान के लिए आगे आना चाहिए।

साफ-सफाई का ध्यान रखना न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए, बल्कि हमारे समाज के समग्र विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण ही हमें एक बेहतर जीवन जीने की ओर ले जा सकता है। इसलिए, जलजमाव जैसी समस्याओं की अनदेखी न करें, और इसे तुरंत साफ करने की पहल करें।

जरूरत है कि हम सामूहिक रूप से इस समस्या के समाधान के लिए आगे आएं। जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, नियमित रूप से सफाई अभियान चलाए जाएं और लोगों को जागरूक किया जाए कि वे अपने घरों और आस-पास के क्षेत्रों में पानी का जमाव न होने दें। तभी हम एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की कल्पना कर सकते हैं, और अपने देश को वास्तविकता में विश्वगुरु बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

indiangreenbuddy@gmail.com

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

वैवाहिक जीवन के सुख और समृद्धि का पर्व है कजली तीज

ज्योतिषाचार्य डॉ अनीष व्यास ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी रक्षा बंधन के तीन दिन बाद कजरी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज को कज्जली तीज भी कहा जाता है।

हरियाली तीज के बाद आने वाली कजरी तीज सुहागिनों के लिए खास होती है। इस दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती के साथ चंद्रमा की पूजा करती हैं। इसे सातूड़ी तीज या बड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। कजरी तीज के दिन सुहागिनें पति की लंबी की कामना के लिए व्रत रखती हैं। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार 22 अगस्त को मनाया जाएगा। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ अनीष व्यास ने बताया कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 21 अगस्त 2024 को शाम 05.06 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 22 अगस्त 2024 को दोपहर 01 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज 22 अगस्त को मनाई जाएगी। यह पर्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित कई राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बूढ़ी तीज व सातूड़ी तीज भी कहा जाता है। जिस तरह से हरियाली तीज, हरतालिका तीज का पर्व महिलाओं को लिए बहुत मायने रखता है। उसी तरह कजरी तीज भी सुहागन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है।

ज्योतिषाचार्य डॉ अनीष व्यास ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी रक्षा बंधन के तीन दिन बाद कजरी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज को कज्जली तीज भी कहा जाता है। हरियाली और हरितालिका तीज की तरह कजरी तीज भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और करवाचौथ की तरह शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस दिन शिव जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कजरी तीज के दिन विधि पूर्वक पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं।

ज्योतिषाचार्य डॉ अनीष व्यास ने बताया कि हरियाली तीज, हरतालिका तीज की तरह कजली तीज भी सुहागन महिलाओं के लिए अहम पर्व है। वैवाहिक जीवन की सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। कहा जाता हैं कि इस दिन जप कन्या या सुहागने पूरे श्रद्धा से अगर शिव भगवान और माता पारवती की पूजा की जाए तो उन्हें अच्छा जीवनसाथी सदा सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है।माना जाता हैं की इस दिन मां पार्वती ने शिव जी को अपनी कठोर तपस्या के बाद प्राप्त किया था। मान्यता है कि कजली तीज के मौके पर विशेष रूप से गौरी की पूजा करें। व्यक्ति की कुंडली में चाहे कितने ही बाधाए क्यों न हों, इस दिन पूजा से नष्ट किए जा सकते हैं। लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब कोई अविवाहिता इस उपाय को खुद करे।

ज्योतिषाचार्य डॉ अनीष व्यास ने बताया कि कजली तीज के बारे में मान्यता है कि आज के दिन ही मां पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त किया था। इसके लिए उन्हें काफी कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। कजरी तीज के दिन सुहागिनों को भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बताया जाता है कि इससे उन कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है, जिनकी शादी नहीं हुई है। पति के साथ और अच्छे रिश्ते बनाने के लिए कुछ ऐसे काम होते हैं, जिन्हें न तो सुहागिनों को करना चाहिए और न ही पति को। ये काम हैं पति या पत्नी से छल, गलत व्यवहार, परनिंदा आदि। पांचवे माह भादों के कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी लड़कियां व्रत करती हैं जो कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कजलीतीन के दिन सुहागिन व्रत रखती हैं। उन्हें आज के दिन श्रृंगार करना चाहिए। इसमें मेहंदी,

चूड़ियां शामिल हैं। वहीं, शाम के समय शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपासना करती हैं। कजली तीज के दिन घर में झूला डाला जाता है और औरतें इसमें झूला झूलती हैं। इस दिन महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ इकट्ठा होती हैं पूरा दिन नाच गाना करती हैं। औरतें अपने पति के लिए और कुवारी लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए व्रत रखती है।

कजरी तीज तिथि

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डॉ अनीष व्यास ने बताया कि पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 21 अगस्त 2024 को शाम 05.06 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 22 अगस्त 2024 को दोपहर 01 बजकर 46 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल कजरी तीज 22 अगस्त को मनाई जाएगी।

पूजा मुहूर्त

भविष्यवक्ता डॉ अनीष व्यास ने बताया कि कजरी तीज पर पूजा भोर का तारा देखकर की जाती है। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 04:26 से प्रातः 05:10 तक रहेगा।

गाय की होती है पूजा

कुंडली विश्लेषक डॉ अनीष व्यास ने बताया कि इस दिन गेहूं, चना और चावल को सत्तू में मिलाकर पकवान बनाएं जाते है। व्रत शाम को सूरज ढलने के बाद छोड़ते है। इस दिन विशेष तौर पर गाय की पूजा की जाती है। आटे की रोटियां बनाकर उस पर गुड चना रखकर गाय को खिलाया जाता है। इसके बाद व्रत तोड़ा जाता है।

पूजन विधि

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डॉ अनीष व्यास ने बताया कि सर्वप्रथम नीमड़ी माता को जल व रोली के छींटे दें और चावल चढ़ाएं। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 13-13 बिंदिया अंगुली से लगाएं। मेंहदी, रोली की बिंदी अनामिका अंगुली से लगाएं और काजल की बिंदी तर्जनी अंगुली से लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मोली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं। दीवार पर लगी बिंदियों के सहारे लच्छा लगा दें। नीमड़ी माता को कोई फल और दक्षिणा चढ़ाएं और पूजा के कलश पर रोली से टीका लगाकर लच्छा बांधें। पूजा स्थल पर बने तालाब के किनारे पर रखे दीपक के उजाले में नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला आदि देखें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें।

कजली तीज व्रत के नियम

कुंडली विश्लेषक डॉ अनीष व्यास ने बताया कि यह व्रत सामान्यतः निर्जला रहकर किया जाता है। हालांकि गर्भवती स्त्री फलाहार कर सकती हैं। यदि चांद उदय होते नहीं दिख पाये तो रात्रि में लगभग 11:30 बजे आसमान की ओर अर्घ्य देकर व्रत खोला जा सकता है। उद्यापन के बाद संपूर्ण उपवास संभव नहीं हो तो फलाहार किया जा सकता है।

व्रत कथा

भविष्यवक्ता डॉ अनीष व्यास ने बताया कि एक गांव में गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने में आने वाली कजली तीज का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी आज मेरा तीज व्रत है। कहीं से मेरे लिए चने का सत्तू ले आइए लेकिन ब्राह्मण ने परेशान होकर कहा कि मैं सत्तू कहां से लेकर आऊं भाग्यवान। इस पर ब्राहमण की पत्नी ने कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर चने का सत्तू चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण रात के समय घर से निकल पड़ा वह सीधे साहूकार की दुकान में गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर सवा किलो सत्तू बना लिया। इतना करने के बाद ब्राह्मण अपनी पोटली बांधकर जाने लगा। तभी खटपट की आवाज सुनकर साहूकार के नौकर जाग गए और वह चोर-चोर आवाज लगाने लगे। ब्राह्मण को उन्होंने पकड़ लिया साहूकार भी वहां पहुंच गया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत रखा है। इसलिए मैंने यहां से सिर्फ सवा किलो का सत्तू बनाकर लिया है। ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मण की पत्नी इंतजार कर रही थी।

साहूकार ने कहा कि आज तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातु, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर अच्छे से विदा किया। सभी ने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे।

माता पार्वती को समर्पित है कजरी तीज

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डॉ अनीष व्यास ने बताया कि माता पार्वती को यह त्योहार समर्पित है। 108 जन्म लेने के बाद देवी पार्वती, भगवान शिव से विवाह करने में सफल हुईं। इस दिन को निस्वार्थ प्रेम के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। कजरी तीज का व्रत रखकर सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। कजरी तीज को कजली तीज, बूढ़ी तीज और सातूड़ी तीज नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत निर्जला किया जाता है। व्रत में स्त्रियां अन्न और जल का त्याग करती हैं। यह व्रत दांपत्य जीवन से जुड़ी परेशानियों को दूर करता है। इस दिन गायों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। व्रत का पारण चंद्रमा के दर्शन करने और उन्हें अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं के साथ कन्याएं भी व्रत रखती हैं। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है तो वहीं कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। माना जाता है कि अगर किसी कन्या के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। इस व्रत में माता गौरी को सुहाग की 16 सामग्री अर्पित की जाती हैं, वहीं भगवान शिव को बेल पत्र, गाय का दूध, गंगा जल, धतूरा आदि अर्पित किया जाता है। इस व्रत में शिव-गौरी की कथा का श्रवण विशेष फलदायी है।

कजरी तीज पर सुहागिन स्त्रियां करें खास काम

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डॉ अनीष व्यास ने बताया कि विवाहित महिलाएं इस दिन दुल्हन की तरह तैयार होकर देवी पार्वती और शंकर जी की पूजा करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस दिन सोलह श्रृंगार कर पूजा करना चाहिए। तीज पर महिलाएं पूजा पाठ के बाद लोकगीत जरूर गाएं। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तीज पर झूला झूलने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।

अगर लेने की सोच रहे गूगल पिक्सेल वॉच 3, बड़ी मुश्किल में फंस से सकते हैं

नई दिल्ली। अगर आप भी गूगल पिक्सल वॉच सीरीज लेने की सोच रहे हैं या आप यूजर्स हैं तो ये खबर आपके लिए है। गूगल पिक्सल वॉच सीरीज यूजर्स के लिए अपने राउंड पेबल डिजाइन को लेकर हमेशा से खास रही है। वॉच का फ्यूचरिस्टिक कर्व्ड ग्लास भी यूजर्स का ध्यान खींचने का काम करता है। लेकिन गूगल पिक्सल वॉच को लेकर सबसे बड़ी परेशानी ही ये है कि एक बार खराब होने पर इसे दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता है।

Pixel Watch 3 की बात करें तो इसके पिछले मॉडल की तरह ही इसस बार भी इस वॉच को रिपेयर किए जाने की खूबी के साथ तैयार नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि अगर आप इस पिक्सल वॉच को खरीदते हैं और भविष्य में आपकी वॉच का डिस्प्ले क्रैक हो जाता है या बैटरी को लेकर किसी तरह की पेरशानी आती है तो इसे चाह कर भी ठीक नहीं करवाया जा सकेगा। एक बार खराब होने के बाद आपकी ये वॉच किसी काम की नहीं रह जाएगी।

पिक्सल वॉच के डिस्प्ले को पहुंच सकता है नुकसान

वॉच के डिस्प्ले को नुकसान पहुंचाने में वॉच का डिजाइन कारण बन सकता है। वॉच का सिग्नेचर राउंड फॉर्म और खूबसूरत कर्व्ड ग्लास इसे आकर्षक तो बनाता है लेकिन साथ ही डिस्प्ले को ज्यादा संवेदनशील भी बना देता है। यानी वॉच के इसी डिजाइन की वजह से वॉच का डिस्प्ले डैमेज हो सकता है। डिस्प्ले को वॉच के गिरने, टकराने से तुंरत नुकसान पहुंच सकता है।

वॉच टूटने पर रिप्लेस का भी बचेगा ऑप्शन

वहीं गूगल ने खुद स्वीकार किया है कि स्मार्टवॉच को लेकर पॉलिसी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर ये वॉच टूट जाती है तो इसे रिप्लेस करे, इसे रिपेयर नहीं किया सकेगा।

नारनौल की इन शानदार जगहों पर घूमकर आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, एक्सप्लोर करें यह जगह

अगर आप दिल्ली एनसीआर के नजदीक कहीं घूमने की जगह की तलाश कर रहे हैं तो आप इस जगह पर जरुर जाएं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित नारनौल, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है। आप यहां पर इन जगहों को जरुर एक्सप्लोर करें।

हरियाणा में स्थित नारनौल के एतिहासिक स्मारक देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और नजदीक ही घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप नारनौल घूमने जाए। इस मौसम में घूमने का एक अलग ही मजा है। इस जगह पर आपको काफी कुछ खास देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं नारनौल के करीब किन जगहों को आप अपने परिवार वालों के साथ और दोस्तों के साथ एक्सप्लोर कर सकती हैं।

जल महल

नारनौल में आप जल महल देखने जा सकते है, जो बेहद खूबसूरत है। इस जल महल को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। कई विदेशी पर्यटक भी इसे देखने के लिए आते हैं। इस महल तक पहुंचने के लिए मेहराब दार पुल बना हुआ है।

छतर्दी

नारनौल मौजूद है छतर्दी एक प्राचीन इमारत है, जो अपने खूबसूरत इमारत के लिए जाना जाता है। बता दें कि यह इमारत मुगलों द्वारा बनवाई गई थी। छतर्दी में शानदार स्तंभ और गुंबद हैं, जो आपको अतीत की समृद्धि की याद दिलाते हैं। यह स्थान इतिहास प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन जगह है।

दर्गाह शाह विलायत

नारनौल की प्रसिद्ध जगहों में से एक है दर्गाह शाह विलायत। इस स्थान की शांति और धार्मिक आस्था यहां के नजारे को और भी खास बनाता है। अगर आप नारनौल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप दर्गाह शाह विलायत जरुर जाएं।

पैरों में कॉर्न मधुमेह का शुरुआती संकेत हो सकता है

पैरों में कॉर्न जैसी आम समस्याएँ, जो ज़्यादातर लोगों की त्वचा पर चुभन के रूप में होती हैं, मधुमेह के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। मधुमेह के मरीज़ कई कारणों से पैरों की जटिलताओं के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, जिनमें खराब रक्त संचार और तंत्रिका क्षति शामिल है, जो पैरों में संवेदना को कम करती है।

पैरों में कॉर्न जैसी आम समस्याएँ, जो ज़्यादातर लोगों की त्वचा पर चुभन के रूप में होती हैं, मधुमेह के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। मधुमेह के मरीज़ कई कारणों से पैरों की जटिलताओं के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, जिनमें खराब रक्त संचार और तंत्रिका क्षति शामिल है, जो पैरों में संवेदना को कम करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति को पैरों की चोट का एहसास नहीं हो पाता है, जैसे कि कॉर्न, जो दबाव या घर्षण के कारण त्वचा के मोटे हिस्से होते हैं। अगर इन कॉर्न का इलाज न किया जाए, तो ये संक्रमण का कारण बन सकते हैं, फिर अल्सर जैसी जटिलताएँ और सबसे खराब मामलों में अंग-विच्छेदन भी हो सकता है।

मधुमेह रोगियों के लिए बचाव के उपाय:

मधुमेह रोगियों को ख़ास तौर पर अपने पैरों पर ध्यान देना चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि पैरों की रोज़ाना जाँच की जानी चाहिए, जैसे कि कॉर्न का बनना। तंग जूते पहनने से बचने के अलावा, पैरों के कुछ हिस्सों पर तनाव कम करने और कॉर्न के विकास से बचने के लिए कुशन वाले जूते भी पहनने चाहिए। साथ ही, सामान्य रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने से तंत्रिका चोट से बचने में मदद मिलती है, और इसलिए, पैर के सामान्य स्वास्थ्य में सुधार होता है।

जब हमने मुंबई के डॉ. एलएच हीरानंदानी अस्पताल के एंडोक्राइनोलॉजी और डायबिटीज़ विभाग के डॉ. अनुराग लीला से बात की, तो उन्होंने कहा कि मधुमेह के रोगियों को पैरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें पैरों को नियमित रूप से धोना, त्वचा को नरम करने के लिए लोशन लगाना, नाखूनों को ठीक से काटना और दुर्घटनाओं से बचने के लिए नंगे पैर चलने से बचना शामिल है। अगर कॉर्न हो जाए, तो कॉर्न को हटाने के लिए शेविंग, कटिंग या कमर्शियल उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। लेकिन सुरक्षित और व्यवहार्य उपचार के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें या आप किसी हर्बलिस्ट से सलाह ले सकते हैं। मधुमेह के रोगियों को हर दिन अपने पैरों की जांच करनी चाहिए, साथ ही, उन्हें नियमित रूप से एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि आगे की जटिलताओं से बचा जा सके और मधुमेह के रोगियों के पैर स्वस्थ और दर्द रहित रहें। यहाँ बस एक बात याद दिलाना है, ऐसी जटिलताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका मधुमेह के पैर की जटिलताओं का जल्दी पता लगाना और उचित प्रबंधन करना है।

जन्माष्टमी के दिन श्रीकृष्ण का पसंदीदा भोग इस तरह से बनाएं, नोट करें इसे बनाने का तरीका

भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव के जश्न मनाने के लिए कुछ ही दिन रह गए। पूरे देश में इस बार 26 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है, तरह-तरह के भोग बनाएं जाते हैं और मदिरों में कई बाल स्वरुप की झांकियां सजाई जाती है। लेकिन इस बार आप श्रीकृष्ण की पसंदीदा भोग आप घर पर बना सकते है। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी।

जन्माष्टमी का त्योहार इस साल 26 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। हिंदु पंचांग के अनुसार, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने धरती पर अवतार लिया था। यही वजह से जन्माष्टमी के दिन सभी मंदिरों में कृष्ण जन्म होता है। इसके लिए मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है। कई घरों में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव होता है। अगर आप भी अपने घर पर कृष्ण जन्म कराने का विचार कर रहे हैं तो आप जन्मोत्सव के बाद धनियां पंजीरी का भोग नन्हें कान्हा को अवश्य लगाएं। इसे बनाना काफी आसान है। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका।

धनिया पंजीरी की सामग्री

-धनिया पाउडर (सूखा धनिया) - 1 कप
-घी - 1/2 कप
-शक्कर - 1/2 कप
-सूखे मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश) - 1/2 कप (कटे हुए)
-मखाने - 1/4 कप
-नारियल का बुरादा - 1/4 कप
-इलायची पाउडर - 1/2 चम्मच

धनिया पंजीरी का बनाने की विधि

- धनिया पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले आप कड़ाही में घी गर्म करें। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें धनिया पाउडर डालें और धीमी आंच पर उसे अच्छी तरह से भूने। धनिया पाउडर भूरा हो जाए तो इसे अलग रख दें।

- फिर आप कड़ाही में थोड़ा और घी डालें और उसमें कटे हुए सूखे मेवे और मखाने को भून लें। जब मेवे सुनहरे हो जाए और मखाने क्रिस्पी दिखने लगे, तब इन्हें भी निकालकर अलग रख दें। फिर धनिया पाउडर में शक्कर मिलाएं।

- इसके बाद आप भुने हुए धनिया पाउडर में शक्कर के अलावा भुने हुई मेवे और नारियल का बुरादा मिलाएं। इस मिश्रण में आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं।

- जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए, तो आपकी धनिया पंजीरी तैयार है। इसे आप भोग लगा सकते हैं। इसे आप कई दिनों पर स्टोर करके भी रख सकते हैं।

भाद्रपद अमावस्या कब है? यह उपाय करने से पितृ दोष से मिलेगा छुटकारा

प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को अमावस्या होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन का विशेष महत्व है। इस बार भाद्रपद अमावस्या को सोमवार पड़ रहा है। इसी वजह से इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। इस दिन व्रत रखने और उपवास आदि करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं।

सोमवती अमावस्या हिंदुओं के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का दिन है, यह तब आता है जब अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर, लोग सुबह पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद व्रत और दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने से नकारात्मक कर्मों का निवारण, शांति की प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति जैसे लाभ मिलते हैं। यह विवाहित जोड़े के जीवन से परेशानियों को दूर रखने में भी मदद करता है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए लाभदायी मानी जाती है। आइए जानते हैं कब है सोमवती अमावस्या, जानें इसका शुभ मुहूर्त।

कब है भाद्रपद अमावस्या

पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद अमावस्या की तिथि का आरंभ 2 सितंबर 2024 को सुबह 5 बजकर 21 मिनट से शुरु होकर समापन अगले दिन 03 सितंबर सुबह 7 बजकर 24 मिनट पर होगा। उदयातिथि के अनुसार व्रत 2 सितंबर 2024 को ही रखा जाएगा। इस दिन सोमवार पड़ रहा है। इसलिए इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है।

भाद्रपद अमावस्या के उपाय

-ज्योतिष शास्त्र में भाद्रपद अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आप नदी में स्नान करते हैं तो आपके कुंडली में कमजोर ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है और देवी-देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

- सोमवती अमावस्या के दिन शादीशुदा लोग वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए व्रत रखते हैं, इससे घर में सुख-शांति आएगी। वहीं, पति के साथ संबंधों में मजबूती आती है।

- पितरों को खुश करने के लिए अमावस्या का दिन सबसे खास होता है। अमावस्या तिथि पर विधिपूर्वक पूजा करने से पितरों का आशीवार्द मिलता है। पितरों को कुशा, फूल और काले तिल जरुर अर्पित करें।

भारत बंद के कॉल का असर दिल्ली में रहा बेअसर

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

अनुसूचित जाति-जनजाति क्रिमीलेयर आरक्षण पर सुप्रीमकोर्ट के फैंसले के खिलाफ बुद्धवार को विभिन्न संगठनों द्वारा भारत बंद के कॉल का असर दिल्ली में रहा बेअसर। राजधानी दिल्ली में बंद की जगह सभी कुछ खुला था दिल्ली मैट्रो, डीटीसी, स्कूल कॉलिज , सरकारी व निजी दफ्तर तक आबाद रहे। राजधानी दिल्ली में राजनीतिक बंद से बेपरवाह लोग अपने दिन प्रतिदिन के काम में बीजी दिखाई दिए। उन पर भारत बंद का कोई असर नहीं पडा। राजधानी दिल्ली के लोगों का तो जवाब ही अलग था। दिल्ली निवासी कैलाश मुंजाल का कहना था, कि इन राजनीतिक नेताओ को मंहगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा ,बलात्कार, लडकियों से छेडछाड, बड़ती आपराधिक वारदातों से अलग जातिगत आधार पर लोगों को लडवाकर अपना उल्लू सीधा करना है। उन्होने कहा कि अनुसचित जाति-जनजाति पर सुप्रीमकोर्ट ने फैंसला सुनाया है। इसमें भारत बंद कर आम लोगों की जिंदगी हराम करने की बजाये सुप्रीमकोर्ट में ही पुनः याचिका दायर करनी चाहिए। ना कि लोगों को परेशानी में डालना चाहिए। एक महिला कमलेश पूनिया ने तो भारत बंद पर यहां तक कह डाला कि बचपन से लेकर अब तक हम भारत बंद के ड्रामे देखते आए है। आम गरीब जनता को शिकार बना कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले ये कथित नेता दुकानों को लूटना, आगजनी करना, सडकों पर उडधंग बाजी करना सब कमर्शियल खेल बन गया है। शाम को ये ही नेता लोग बंद कितना सफल और मीडिया में छाने की वाहवाही लूटने और शराब पार्टी एक धंधा बन गया है। कुछ अपराधी तत्वों की कमर्शियल जमात के भरोसे अपनी दमगई दिखाने का मौका ये कथित नेता नहीं छोडते है। महिला ने तो यहां तक कह डाला कि ऐसी बंद की उडधंग बाजी में बेकसूर लडकियां इनका शिकार बन जाती है। बहरहाल राजधानी दिल्ली के तमाम बाजार खुले थे। अर्वतिका, एंव फेडरेशन आफ रोहिणी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय पाल ने बताया कि पूरी रोहिणी मार्किट खुली हुई है। कारोबार पूरे जोर पर है। भारत बंद का कोई असर नहीं है। ,फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा, राजेश यादव ने बताया कि सदर बाजार, खारी बाउली, दरिबा, चांदनी, लाजपत नगर, सरोजनी नगर मार्किट आदि सभी बाजार आम दिनों की तरह आबाद है। कहीं से भी भारत बंद जैसी सुगबुगाहट दिखाई नहीं दी। इसी तरह सीटीआई चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के तहत आने वाले 700 बाजार पूरे शानो शौकत से खुले थे। उल्लेखनीय है कि अनुसचित जाति-जनजाति क्रीममलेयर आरक्षण पर सुप्रीमकोर्ट के फैंसले के खिलाफ विभिन्न संगठनों, जिनमें भीम सेना, बहुजन दलित समाज, समेत नेशनल कन्फेडरेशन आफ दलित एंड आदिवासी, आर्गनाइजेशन (NACDAOp), अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ मोर्चा, ने 21 अगस्त को भारत बंद की कॉल की थी बंद के नाम पर सिर्फ इसका कुछ असर राजस्थान, बिहार, और एम पी में तो दिखाई दिया, लेकिन राजधानी दिल्ली में ऐसे किसी बंद को लेकर कोई गंभीरता नही दिखी। सब सामान्य रहा।

स्टूडेंट्स दबाव से 2 शिफ्ट में चलता था स्कूल लेकिन नए स्कूल ब्लॉक से दोबारा सिंगल शिफ्ट में चलेगा स्कूल

सुषमा रानी

नई दिल्ली। शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए केजरीवाल सरकार ने मैदानगढ़ी गाँव की संकरी गलियों के बीच गवर्नमेंट को-एड सेकेंड्री स्कूल में एक शानदार चार मंज़िला स्कूल ब्लॉक का निर्माण करवाया है। बुधवार को शिक्षा मंत्री आतिशी ने उद्घाटन कर इसे बच्चों को समर्पित किया। इस मौक़े पर शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, मैदानगढ़ी गाँव के स्कूल में टूटे जर्जर क्लासरूम की जगह बना ये स्कूल ब्लॉक अब महँगे प्राइवेट स्कूलों की बिल्डिंग से भी शानदार है।

उन्होंने कहा कि, चार मंज़िला नए स्कूल ब्लॉक से मैदानगढ़ी, राजपुर, छत्तरपुर, नेब सराय सहित आसपास के हज़ारों बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। बता दें कि, स्टूडेंट्स का दबाव बढ़ने से ये स्कूल 2 शिफ्ट में चलता था लेकिन नए स्कूल ब्लॉक से ये दोबारा सिंगल शिफ्ट में चलेगा। चार मंज़िला ये नया स्कूल ब्लॉक लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम से लैस है।

शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने विज़न से दिल्ली में शिक्षा की तस्वीर बदल दी और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के ज़रिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आगे बढ़ने का मौक़ा दिया। उन्होंने साझा किया कि, आज़ादी से 2015 तक की सरकारों ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मात्र 24,000 कमरे बनवाये लेकिन पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल सरकार ने 22,000 से ज़्यादा क्लासरूम बनवाए।

केजरीवाल सरकार देश की पहली ऐसी सरकार बनी जिसनें अपने शिक्षकों को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा; हमनें टीचर्स ट्रेनिंग का बजट 10 गुणा बढ़ाया।

उन्होंने कहा कि, दिल्ली में आज ग़रीब परिवार का बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर बन रहा है; बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है और अपने परिवार को ग़रीबी से बाहर निकाल रहा है, ये अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति है। अरविंद केजरीवाल ने ग़रीब परिवार के बच्चों को शानदार शिक्षा देकर उनका भविष्य संवारने का प्रयास किया इसलिए उन्हें जेल में डाला गया। लेकिन दिल्लीवालों के प्यार और आशीर्वाद से जल्द अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आयेंगे और मौजूदा स्कूल में एक और नए ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे।

शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, मैदानगढ़ी गाँव की संकरी गलियों में जहां गाड़ियों का निकलना मुश्किल है, उसमे शानदार 4 मंज़िला स्कूल ब्लॉक बनवाने का काम सिर्फ़ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ही कर सकती है। एक ऐसे गाँव में जहां जगह की कमी रही, स्कूल बिल्डिंग पर दबाव रहा वहाँ के लिए ये नया स्कूल ब्लॉक बहुत महत्वपूर्ण है।

शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, इस शिक्षा क्रांति की शुरुआत 2015 में हुई थी। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रण लिया कि, दिल्ली के हर बच्चे को चाहे वो अमीर परिवार से या ग़रीब परिवार से आता हो, उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए।

शिक्षा मंत्री आतिशी ने साझा करते हुए कहा कि, देश की आज़ादी के बाद से 2015 तक की सरकारों ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मात्र 24000 कमरे बनवाये। लेकिन पिछले 10 साल में ही अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 22,000 से ज़्यादा क्लासरूम दिल्ली के बच्चों के लिए बनवा दिए। पिछले 10 सालों में छत्तरपुर विधानसभा में ही 14 नई स्कूल बिल्डिंग बनी है

आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर-इंजीनियर, आईएएस अफ़सर बन रहे है। हर साल हमारे स्कूलों के 1000 से ज़्यादा बच्चे जेईई-नीट क्वालीफाई कर आईआईटी और बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन ले रहे है। एक पीढ़ी में ही अपने परिवार की ग़रीबी से बाहर निकाल रहे है।

उन्होंने कहा कि, इस सरकार का एक ही सपना है कि, चाहे बच्चा अमीर परिवार में पैदा हुआ हो या ग़रीब परिवार में उसे आगे बढ़ने का मौक़ा मिलना चाहिए। हर बच्चे को इस देश को आगे बढ़ाने का मौक़ा मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि, दिल्लीवालों के प्यार और आशीर्वाद में इतनी ताक़त है कि, अरविंद केजरीवाल जल्दी जेल से बाहर आयेंगे और पूरी ताक़त से दिल्लीवालों के काम करेंगे। और इस स्कूल में एक और नये बिल्डिंग ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल इसका शिलान्यास करेंगे।

ट्रेन की टॉयलेट में नींद, आईये भारतीय रेल में स्वागत है

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। इन दिनों त्यौहारों के सीजन में भारतीय रेल की बोगियों में भीड ने यात्रियों को टॉयलेट तक में सफर ही नहीं नींद तक लेने को मजबूर कर दिया है। कहने को तो रेलवे ने फर्राटेदार ट्रेनों को पटरियों पर तो उतार दिया है , लेकिन आज भी एक आम आदमी के हद से बाहर सुकून का सफर मयैस्सर नहीं हो पाया है। किराया देने के बाद भी उसके आराम के सफर का मौलिक अधिकार नहीं मिल पाया है। उमस भरी गर्मी में जर्नल डिब्बे की भीड में खडे होकर सफर करना बेहद हिम्मत का काम है। आजादी के 78 वर्ष के बाद भी गुलामों की तरह का जीवन जीना हमारी भारतीय रेल को कतई शोभा नही देता है। सरकार और रेल मंत्रालय को गरीबों को बेहतर सुविधाए मुहैया होनी चाहिए। रेलगाडियां सिर्फ अमीरों के सफर के लिए ही नहीं है। सरकार को चाहिए कि आम जनता की सहुलियत के मद्देनजर जनरल बोगियों की संख्या को बढाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया में यह तस्वीर पूरे विश्व में वायरल है। उनकी नजर में भारत की छवि कितनी खराब बनेगी। जबकि भारत ने चांद पर पहुंचकर अपनी वर्ल्ड में

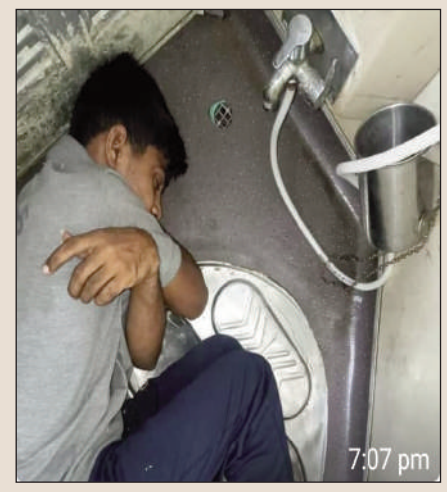

खासी ईमेज तो बना ली। क्या धरती पर जीने के मौलिक अधिकार को भारतीय रेल अपनी रेलगाडियों में दे पाएगा। जिससे उसके यात्री कम से कम टॉयलेट में सोने को मजबूर न हो।

दिल्ली सरकार से पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति न होने पर फोरम ने कुलपति से की मांग

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध दिल्ली सरकार से पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों के सामने पिछले कई साल से जहाँ सैलरी , शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति न होना व पदोन्नति के बाद उनका एरियर न मिलना , समय पर मेडिकल बिल पास न होना आदि समस्याओं से शिक्षक जूझ रहे हैं । वहीं इन 12 कॉलेजों में एक दशक से शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू न होने के कारण छात्रों की शिक्षा पर असर पड़ रहा है । बता दें कि जो तदर्थ शिक्षक लंबे समय से सरकार के इन कॉलेजों में पढ़ा रहे थे इन दो सालों में वे दूसरे कॉलेजों में स्थायी होकर चले गए है । दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों से शिक्षकों की संख्या लगातार घट रही है और यहाँ पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है । बताया जा रहा है कि 200 से अधिक शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों व दिल्ली से बाहर के विश्वविद्यालयों / कॉलेजों में हो जाने के कारण बहुत कम तदर्थ शिक्षक बचे है । स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि अतिथि शिक्षकों (गेस्ट टीचर्स) के सहारे कॉलेज चल रहे है । फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह से कॉलेजों में पुनः एडहॉक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है ताकि छात्रों की शिक्षा पर असर न पड़े । साथ ही फोरम ने दिल्ली सरकार से शत प्रतिशत वित्त पोषित 12 कॉलेजों में भी रोस्टर रजिस्टर विश्वविद्यालय प्रशासन से पास कराकर स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की है ।

फोरम के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन का कहना है कि दिल्ली सरकार का उच्च शिक्षा मॉडल एक दिखावा बनकर रह गया है । दिल्ली सरकार की फंड कटौती , निजीकरण/स्व-वित्त पोषण नीति के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कसने का समय आ गया है। इस नीति ने दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित 12 कॉलेजों को वित्तीय दृष्टि से दयनीय स्थिति में बदल दिया है। उन्होंने बताया है कि पिछले पांच वर्षों में 50 प्रतिशत तक फंड कटौती के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि इन कॉलेजों को बंद होने का सामना करना पड़ सकता है। डीयू के ये कॉलेज 10 साल या उससे अधिक समय से शिक्षकों या गैर-शिक्षण कर्मचारियों की एक भी स्थायी नियुक्ति नहीं कर सके। जबकि डीयू के अन्य 53 कॉलेजों ने पिछले दो वर्षों में नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन कॉलेजों में लगभग 4700 शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति हो चुकी है और अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है । उन्होंने बताया है कि अदिति महाविद्यालय , दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज , भाष्कराचार्य कॉलेज व आचार्य नरेन्द्रदेव कॉलेज आदि कॉलेजों ने शिक्षकों के स्थायी पदों का विज्ञापन जारी कर दिया है लेकिन बाकी 8 कॉलेजों ने अभी तक रोस्टर रजिस्टर तैयार नहीं किया है और न ही विज्ञापन जारी किए है ।

डॉ. सुमन ने बताया है कि इस शैक्षणिक सत्र में छात्रों की लगभग 50 प्रतिशत कक्षाएं प्रभावित होने या बिल्कुल भी आयोजित नहीं होने की संभावना जताई है। उन्होंने यह भी बताया है कि इन कॉलेजों में 1512 शिक्षकों की आवश्यकता के मुकाबले केवल 824 शिक्षक (528 स्थायी और 296 तदर्थ शिक्षक) हैं। इन कॉलेजों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भी यही स्थिति है, 1366 की आवश्यकता के स्थान पर केवल 483 स्थायी और 285 संविदा कर्मचारी (कुल 728) हैं। इन कॉलेजों में प्रयोगशालाएँ, कार्यालय, पुस्तकालय, सामान्य रखरखाव आदि सभी बुरी तरह प्रभावित हैं और इन संस्थानों को चलाना भविष्य में असंभव होता जा रहा है। इन कॉलेजों में छात्र, शिक्षक , कर्मचारी सबसे अधिक प्रभावित हैं। शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है । जबकि कॉलेज लगभग आधी क्षमता पर चल रहे हैं। अगर सभी शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति समय पर होती तो सरकार अनुदान न देने के नाम पर कॉलेजों से पल्ला झाड़ लेती । उन्होंने यह भी बताया है कि शिक्षकों और कर्मचारियों को फंड की कमी के कारण लंबे समय से लंबित बकाया, मेडिकल बिल, एलटीसी आदि का भुगतान नहीं किया जाता है। समस्या विकराल होती जा रही है इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय को दिल्ली सरकार द्वारा अनुचित फंड कटौती के मुद्दे पर अकादमिक परिषद व कार्यकारी परिषद की विशेष बैठक बुलाई जाने को लेकर फोरम कई बार लिख चुका है । विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों , कर्मचारियों व शिक्षकों की समस्याओं को देखते हुए बृहस्पतिवार (आज) को विद्वत परिषद की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें सरकार के कॉलेजो को लेकर निर्णय लिया जायेगा । डॉ. सुमन ने बताया है कि दिल्ली सरकार से संबद्ध पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों के अतिरिक्त 20 अन्य कॉलेज (16 प्रातः और 4 सांध्य) हैं जो यूजीसी के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा उनका रखरखाव किया जाता है। इन कॉलेजों ने अपने यहाँ स्थायी शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और समय पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है, इन कॉलेजों का लगभग सभी बकाया और देय राशि का भुगतान समय पर किया जा रहा है।

देश के न्यायालयों को भी महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में त्वरित न्याय देने की ओर ध्यान देना चाहिए- प्रीति तोमर

सुषमा रानी

नई दिल्ली, कोतकाता समेत देश भर में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और बलात्कार की घटनाओं से आहत आदमी पार्टी ने बुधवार को इसके खिलाफ मोर्च खोल दिया। पीड़ति महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार से कड़े कानून बनाने की मांग करते हुए ''आप'' दिल्ली महिला मोर्च के सदस्यों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की अध्यक्ष सारिका चौधरी और विधायक प्रीति तोमर के नेतृत्व में ''आप'' की महिला पार्षद और कार्यकर्ता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर शांति प्रार्थना सभा में भाग लिया और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान महिला विंग ने कहा कि महिला अत्याचार के मामले में सभी पार्टियों को राजनीति करने के बजाय एकजुट होना चाहिए और महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले दोषियों को सख्त सजा दिलाने पर जोर देना चाहिए। साथ ही, ऐसे जघन्य अपराधों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए और दोषित को छह महीने में मौत की सजा दिलाई जानी चाहिए।

कोलकाता में हुई घिनौनी घटना और देशभर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार तथा बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ, पीड़ति महिलाओं को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने राजघाट स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित कर प्रदर्शन किया। ''आप'' की महिला विंग द्वारा आयोजित शांति प्रार्थना सभा में विधायक प्रीति तोमर, धनवती चंदेला और राज्य महिला विंग की अध्यक्ष

सारिका चौधरी समेत अन्य महिला पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हुईं। इस दौरान महिला विंग ने 'महिलाओं पर अत्याचार, नहीं सहेगा हिन्दुस्तान, हत्यारे को फांसी दो, देश की बेटी को न्याय दो' के जमकर नारे लगाए।

आम आदमी पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष सारिका चौधरी ने कहा कि देश में जिस तरह महिलाओं के साथ घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे हम बहुत दुखी हैं। चाहे वह पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या देश के किसी भी हिस्से में हो रही हों। हम हर रोज अखबार में बलात्कार की खबरें पढ़ते हैं। आज छोटी-छोटी बच्चियों के साथ भी बलात्कार हो रहा है। केंद्र सरकार को इस पर सख्त कानून बनाना चाहिए। बच्चों के साथ ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। छह महीने के भीतर अपराधियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह देश के किसी भी हिस्से में हो। हम चाहते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द जांच करके आरजी कर अस्पताल की घटना के तथ्यों का पता लगाए। हमारी मांग है कि जो भी इस घटना में शामिल हो, उन्हें मौत की सजा होनी चाहिए।

इस दौरान ''आप'' विधायक प्रीति तोमर ने कहा कि हमने गांधी के सामने अत्याचार की शिकार बेटी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दरिंदों को एक दिन सजा तो मिल ही जाएगी, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या एक मां-बाप की बेटी वापस आ जाएगी। इस तरह से रेप की घटना को अंजाम देना और उसके बाद उसकी हत्या कर देना, आज 12 साल बाद दूसरी निर्भया का केस हमारे सामने आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह डॉक्टर थीं और यह घटना अस्पताल के अंदर हुई। ऐसे दरिंदों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। सवाल यह नहीं है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बल्कि सवाल यह है कि महिलाओं के साथ हो रहे ऐसे अपराधों की गिनती भी पूरी तरह से नहीं हो पाती है। क्योंकि न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं और इतने समय में और कई घटनाएं हो जाती हैं। ऐसे में इन अपराधियों के मन में डर कैसे बैठेगा? पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, और अगर हो भी जाती है तो अपराधी जल्द ही जमानत पर छूट जाते हैं या फिर धमकियों के चलते घटनाओं को दबा दिया जाता है। आज मां-बाप अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कुछ घटनाएं दबा दी जाती हैं और कई मामले सामने भी नहीं आते।

प्रीति तोमर ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द सख्त कानून बनाकर लागू करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। राजनीति बाद में भी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। हमारे देश में पहले से ही कई कानून हैं, परंतु उन पर अमल नहीं होता है। न्यायालयों को भी इस दिशा में त्वरित न्याय देने की ओर ध्यान देना होगा।

अडानी पर रिपोर्ट की पुनः जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कल जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेगी: देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली, प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अडानी ग्रुप जुगलबंदी के बाद सामने आया महाघोटाला जिसका हिडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सेबी की अध्यक्ष माधबी बुच और उनके पति धवल बुच ने गौतम अडानी के दो आफशोर फंड की हिस्सेदारी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट से छिपाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी द्वारा किए गए हजारों करोड़ के महाघोटाले की जांच की जिम्मेदारी सेबी अध्यक्ष माधबी बुच को सौंपी, जिसमें मोदी सरकार के दबाव पर अडानी ग्रुप को बचाने की कोशिश की गई। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में उठाए सवालों और अडानी ग्रुरप के साथ सेबी अध्यक्षता की संलिप्तता की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर दिल्ली प्रदेश कांगेस कमेटी कल 22 अगस्त, 2024 को सुबह जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक विशाल धरना प्रदर्शन करेगी। जिसमें कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्व वरिष्ठ नेता, दिल्ली कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाओं और दिल्ली के प्रभावित लोग धरने में हिस्सा लेंगे।

संवाददाता सम्मेलन को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव, अ0भा0क0कमेटी के सोशल मीडिया एवं डिजीटल प्लेटफार्म विभाग की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनते और प्रदेश कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने संबोधित किया।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और जनप्रिय नेता राहुल गांधी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान देश में अमीरों का और अमीर होना और गरीबों के और गरीब होने पर चिंतित है। देश में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि जब देश की, देश की सम्पति उसकी सुरक्षा को जिसके हाथों में जनता सौंपती है, जब वही भेड़िया बनकर उसको खाने की भूमिका निभाऐगा तो देश को कौन बचाऐगा। हिडनबर्ग की रिपोर्ट, अडानी ग्रुप की गतिविधियों की सेबी की जांच, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और अडानी को भरपूर समर्थन देने सहित पोषित करने की भूमिका मोदी जी निभा रहे है। उन्होंने कहा कि अडानी के महाघोटाले को देशवासियों तक पहुँचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद लड़ाई लड़ेगी।

अ0भा0क0कमेटी के सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफार्म विभाग की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनते ने संवाददाता

सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अडानी महाघोटाले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सेबी द्वारा जांच के बाद सेबी अध्यक्षा माधबी बुच की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग गया है जिसमें अडानी को मोदी जी के संरक्षण में बचाने की कोशिश की गई है। अडानी के महाघोटाले की परत दर पर खुलने पर मोदी सरकार का भ्रष्टाचार देशवासियों के सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि अडानी को फायदा पहुँचाने के लिए मोदी जी सीबीआई, ईडी सहित अन्य सरकारी एजेंसियों का इतनी सफाई से इस्तेमाल कर रहे है कि शेयर बाजार सहित देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, बिजली संस्थान सहित देश का पूरे बिजनेस अडानी को दिया जा रहा है, अगर कोई अन्य प्रतियोगी अडानी के समक्ष आता है तो मोदी सरकार की सरकार जांच एजेंसी अडानी के लिए उनपर छापेमारी करना शुरु कर देती है। मोदी सरकार अडानी ग्रुप पर पूरी तरह मेहरबान है।

श्रीनते ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरे और सरकार की विदेश नीति सब कुछ अडानी के लिए हो चुका है।प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद श्रीलंका में अडानी ग्रीन एनर्जी पावर परचेज एग्रीमेंट 20 साल के लिए 367 करोड़ निवेश करेगी। बंगलादेश में अडानी ग्रुप इलेक्ट्रो पावर का एग्रीमेंट मिला और इसी तरह इजरायल में प्रधानमंत्री दौरे के बाद अडानी को बिजनेस मिला। मतलब मोदी सरकार की विदेश नीति अडानी के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चल रहे है। उन्होंने कहा कि सरकार अडानी को व्यापार बढ़ाने के लिए सभी हदें पार कर रही है। आज दो रुपये की चीज 20 रुपये में मिल रही है। उन्होंने कहा कि अब सवाल उठता है जिसकी रक्षा और सुरक्षा खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे है उसकी जांच कौन करेगा।

सुप्रिया श्रीनते ने कहा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट में हजारों करोड़ के अडानी महाघोटाले की जांच कर रही सेबी अध्यक्ष माधबी बुच जिन कम्पनियां में अडानी के खिलाफ जांच कर रही है, उन कम्पनियों में माधबी बुच और उनके पति धवल बुच की राशि लगी है और धवल बुच कम्पनियों के एडवाईजर भी है। उन्होंने कहा कि माधबी बुच को सेबी अध्यक्ष पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। निवेशकों के हजारों करोड़ के नुकसान का हर्जाना कौन भरेगा, क्योंकि माधबी बुच ने सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नही लाया कि कम्पनियों में उनकी भी हिस्सेदारी है जिनकी वो जांच कर रही है। आज सवाल उठता है कि मोदी जी आखिर कब तक अडानी को बचाऐंगे।

तस्वीरों में देखें दिल्ली-NCR में कैसा रहा भारत बंद का असर, सुरक्षा के बीच खुले स्कूल-बाजार

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली- एनसीआर में बुधवार को भारत बंध का कोई असर नहीं दिखा। रोजाना की तरह स्कूल दुकान और फैक्ट्री खुली। नोएडा में भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) शिवहरी मीना ने सेक्टर 18 27 मार्केट में पुलिस फोर्स के पैदल मार्च निकाला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस को सर्तकता के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया गया।

नोएडा/गाजियाबाद/गुरुग्राम। दिल्ली-एनसीआर में भारत बंद का असर नहीं रहा। सभी बाजार खुले रहे। सड़कों पर यातायात व्यवस्था सामान्य रही। बाजार संगठनों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह भारत बंद में सहभागी नहीं होंगे।

चैंबर आफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि इस संबंध में किसी आंदोलनकारी संगठनों ने इस संबंध में समर्थन के लिए दिल्ली के बाजार संगठनों से संपर्क भी नहीं किया था। इसलिए दिल्ली के सभी 700 बाजारों के साथ सभी 56 औद्योगिक क्षेत्रों में भी गतिविधियां सामान्य रही।

रोजाना की तरह खुले स्कूल-बाजार

बहुजन समाज पार्टी के भारत बंद का गाजियाबाद में कोई खास असर देखने को नहीं मिला। कई दिन से स्थानीय कार्यकर्ता भीड़ जुटाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कई हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद से बहुत कम लोग इस प्रदर्शन में पहुंचे। कार्यकर्ताओं में जोश जरूर दिखा।

एससीएसटी आरक्षण बचाने की मांग को लेकर बसपा ने भारत बंद की घोषणा की थी। तय कार्यक्रम के अनुसार बुधवार 11 बजे आरडीसी स्थित बसपा कार्यालय से जिला अध्यक्ष दयाराम सैन की अगुवाई में लोग कलेक्ट्रेट की तरफ पैदल मार्च करते हुए निकले।

केंद्र सरकार के खिलाफ के नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता सड़क पर निकले तो यातायात जाम हो गया। बाद में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम प्रेषित ज्ञापन डीएम को सौंपा।

इस मौके पर वीरेंद्र सिंह ,रवि जाटव , पंकज शर्मा, गंगा शरण, बबलू , बाबूलाल सेन , प्रमोद सागर , मुनव्वर चौधरी ,ओमवीर मौजूद रहे। इसके अलावा कालका गढ़ी चौक से अंबेडकर रोड होते हुए आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी पैदल मार्च निकाला। कार्यकर्ता सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे।

नोएडा में भारत बंद का नहीं दिखा असर

देशभर में कुछ संगठनों द्वारा भारत बंद का नोएडा में कोई खास असर देखने को नहीं मिला। शहर में जीवन सामान्य रूप से चलता रहा और फैक्ट्री, कंपनी, बाजार, कार्यालय तथा स्कूल नियमित रूप से खुले रहे।

नोएडा के प्रमुख बाजारों जैसे सेक्टर 18, अट्टा मार्केट और अन्य व्यावसायिक इलाकों में भीड़भाड़ सामान्य दिनों की तरह ही रही। कहीं भी दुकानें बंद होने की सूचना नहीं मिली।

यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रही और शहर में किसी प्रकार की अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन शांति और सामान्य स्थिति को देखते हुए किसी प्रकार की बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी।

चप्पे-चप्पे पर पुलिस रही तैनात

स्थानीय निवासियों ने भी बंद को लेकर उदासीनता दिखाई और अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहे। शहर में बंद का कोई असर न होने से व्यापारियों और आम जनता ने राहत की सांस ली। कुल मिलाकर शहर में भारत बंद के आह्वान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और शहर की दिनचर्या सामान्य रूप से जारी रही।

वहीं भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) शिवहरी मीना ने सेक्टर 18, 27 मार्केट में डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह, डीसीपी अनिल यादव, एडीसीपी मनीष मिश्र के साथ पुलिस फोर्स के पैदल मार्च निकाला। सुरक्षा व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए सर्तकता के साथ ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

भारत बंद का गुरुग्राम में कोई असर नहीं

एससी-एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई संगठनों ने बुधवार को भारत बंद बुलाया था, लेकिन गुरुग्राम में इसका कोई असर नहीं दिखा। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से विजय खटाना के नेतृत्व में कई लोगों ने डीसी को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा।

शहर में किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। हालांकि, इसको लेकर पहले से ही गुरुग्राम पुलिस की तैयारी थी। पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर कहा था कि कानून व्यवस्था को बाधित करने वाले असामाजिक तत्वों पर पूरी तरह से नजर रखी जाएगी।

आम जनों से भी अपील की थी कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। जिले के स्कूल खुले रहे। सुबह ही बच्चे स्कूल पहुंच गए थे। किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। शहर के बाजार भी खुले हुए हैं।

अवैध कॉलोनी ध्वस्त करने पहुंची GDA की टीम बैरंग लौटी, लोगों ने विरोध के चलते नहीं हो सकी कार्रवाई

जीडीए प्रवर्तन टीम जब अवैध कॉलोनी ध्वस्तीकरण के लिए बुल्डोजर लेकर पहुंची तो पहले तो काफी हंगामा और विरोध किया गया। इसके बाद बात न बनती दिखी तो सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो में एक व्यक्ति नोट की गड्डी लेकर जीडीए टीम के एक-एक व्यक्ति के पास पहुंचा और वीडियो बनाते हुए देने का प्रयास करते हुए दिखाई दिया।

गाजियाबाद। जीडीए प्रवर्तन जोन-तीन क्षेत्र के गांव मटियाला के पास करीब 15 बीघा भूमि में अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी। इसकी सूचना मिलने पर जीडीए प्रवर्तन दल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन कालोनाइजर के समर्थन में कुछ अधिवक्ता भी पहुंच गए।

जीडीए टीम के साथ की गई अभद्रता

इस बीच कुछ जीडीए टीम के साथ अभद्रता भी की गई। आखिरकार भारी विरोध के चलते प्रवर्तन दल को बैरंग लौटना पड़ा। मंगलवार को जीडीए प्रवर्तन दल की टीम जोन-तीन के मटियाला गांव के निकट काटी जा रही अनाधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त करने के लिए जीडीए प्रवर्तन जोन के सहायक अभियंता अनिल शर्मा, अवर अभियंता राजेंद्र कुमार, जीडीए पुलिस और मधुबन-बापूधाम पुलिस के साथ पहुंची।

जीडीए टीम ने जैसे ही बुलडोजर से सड़क को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की। तभी कालोनाइजर और उनके साथियों के साथ कुछ अधिवक्ताओं ने भी विरोध किया। काफी देर तक टीम के साथ बहस करने के बाद जमकर हंगामा किया गया।

बगैर नोटिस के निर्माण नहीं तोड़ने देंगे

इस दौरान कई अधिवक्ता कालोनाइजर के समर्थन में वहां पहुंच गए और जीडीए टीम का जमकर विरोध किया। उन्होंने जीडीए के इंजीनियरों से नोटिस दिए जाने की मांग की। वकीलों ने कहा कि बगैर नोटिस के सड़क व अन्य निर्माण नहीं तोड़ने देंगे।

इसी बीच अधिवक्ताओं और जीडीए प्रवर्तन दल व पुलिस बल के साथ अभद्रता भी की गई। कड़े विरोध के चलते आखिरकार जीडीए टीम को बिना कार्रवाई बैरंग लौटना पड़ा।

जल्द ही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया जाएगा

"मटियाला में अवैध रूप से कॉलोनी काटी जा रही है। वहां के लोगों ने विरोध किया। मामला संज्ञान में है। जल्द ही अगली तारीख निर्धारित करते हुए अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया जाएगा और अभद्रता करने वालों को चिह्नित कर लिया गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।"

'यूपी के उपचुनाव में सपा करेगी बड़ा उलटफेर', नोएडा पहुंचे धर्मेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा में एक कार्यक्रम में पहुंचे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को उपचुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। धर्मेंद्र ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करनी होगी। वहीं भारत बंद को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। पढ़िए आखिर उन्होंने और क्या-क्या कहा है?

नोएडा। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) पूरी ताकत झोंक रही है। सपा लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी अपना प्रदर्शन अच्छा करना चाहती है। सपा ने लोकसभा चुनाव में यूपी में 80 में से 37 सीटें जीतकर जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई थी। सपा को उपचुनाव में भी अधिक से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद है।

वहीं, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बुधवार को नोएडा पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। यह कार्यक्रम सेक्टर 33 में आयोजित हुआ, जहां संविधान मानस्तंभ की स्थापना एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया था।

इस गोष्ठी में धर्मेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने संविधान के महत्व पर बल दिया। इस अवसर पर पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह भी मौजूद थीं।

कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करनी होगी

धर्मेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2027 विधानसभा चुनावों के लिए मेहनत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी की नजर नोएडा की तीनों विधानसभा सीटों पर है और उन्हें जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को कड़ी मेहनत करनी होगी।

सपा आगामी चुनावों में बड़ा उलटफेर करेगी

वहीं, कार्यक्रम के दौरान सांसद धर्मेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों पर भी अपनी बात रखी और दावा किया कि समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि पार्टी जनता के समर्थन से आगामी चुनावों में बड़ा उलटफेर करेगी।

वंचितों के साथ हो रहे अन्याय पर चिंता जताई

सांसद ने 'भारत बंद' के समर्थन पर भी खुलकर अपनी राय रखी और कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस बंद का समर्थन करती है। उन्होंने समाज के दबे-कुचले लोगों और वंचितों के साथ हो रहे अन्याय पर चिंता जताई और कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और उनके हक के लिए संघर्ष करेगी।

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हिस्सा लिया और सांसद धर्मेंद्र यादव के विचारों का समर्थन किया।

सामाजिक समरसता से बनेगा सशक्त भारत

प्रो. संजय द्विवेदी

यानि जन्म से आप 'आदमी' हो सकते हैं किंतु 'मनुष्य' या 'इंसान' एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही आप बनते हैं। हमारे समाज में मनुष्य बनाने के स्कूल थे। हमारा परिवार, समाज और विद्यालय तथा धर्मगुरु इस प्रक्रिया को संभव करते थे।

समता, ममता और समरसता हमारे भारतीय लोकजीवन का अभिन्न अंग है। हम जिस देश में रहते हैं उसके ऋषि कहते हैं- 'सर्वभूतहिते रताः।' प्रकृति से साथ हमारा संवाद बहुत पुराना है। इसलिए हमने अपनी समूची सृष्टि को स्वीकारा। किसी को विरोधी नहीं माना। पेड़, पहाड़, नदियां, समुद्र, वनस्पतियां, जलचर, नभचर, जीव-जंतु, मनुष्य सबमें ईश्वर का वास मानने वाले हम ही हैं। हम ही कह पाए जो जड़ में है वही चेतन में है। कण-कण में ईश्वर का वास मानने वाली संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है।

काल के प्रवाह में विचलन स्वाभाविक है। आज हमें समता, समरसता और अधिकारों की बात करनी पड़ रही है। सुधारों की बात करनी पड़ रही है, क्योंकि विचलन ने हमें उन मूल्यों से विरत कर दिया, जहां एक आदमी को ईश्वर बन जाने की स्वतंत्रता थी। आदमी का मनुष्य बनना और फिर देवत्व की तरफ बढ़ना साधारण नहीं है। उसके मूल्यनिष्ठ होते जाते की मुनादी है, घोषणा है। ऋषि कहते हैं- 'मर्नु भवः' यानि मनुष्य बनो। यही बाद बाद में गालिब के मुंह से निकलती है-

यूं तो मुश्किल है हर काम का आसां होना
आदमी को मयस्सर नहीं इंसा होना।

यानि जन्म से आप 'आदमी' हो सकते हैं किंतु 'मनुष्य' या 'इंसान' एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही आप बनते हैं। हमारे समाज में मनुष्य बनाने के स्कूल थे। हमारा परिवार, समाज और विद्यालय तथा धर्मगुरु इस प्रक्रिया को संभव करते थे। मनुष्य-मनुष्य में भेद को हमने अपराध माना। इसीलिए गुरू घासीदास कहते हैं- मनखे-मनखे एक हैं। इसी बात को गांधी छुआछूत के संदर्भ में कहते हैं- "अस्पृश्यता ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है।" हिंदू समाज में आई जड़ता को तोड़ने के लिए समय-समय पर सुधारवादी आंदोलन चलते रहे हैं। हिंदु स्वयं एक ऐसा समाज है, जिसने अपने आत्मसुधार के लिए निरंतर यत्न किए हैं। हम सब ऋषियों की संतति हैं यह भाव लेकर काम करते रहे हैं। गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, कबीर, नानक, गुरू गोरखनाथ, गुरू घासीदास, संत रविदास से लेकर एक पूरी परंपरा जड़ताओं और कुरीतियों पर प्रहार करते हुए आत्मालोचन के लिए प्रेरित करती रही है। समय के सच को समझना और अपने समय के कठिन सवालों से जूझना हिंदुत्व की प्रकृति रही है। गुलामी के कालखंड में आई कुछ नकारात्मक वृत्तियों को समाप्त करने के लिए राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, बाबा साहब डा.भीमराव आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पंडित सुंदरलाल शर्मा जैसे अनेक नायक हमारे समाज में समरसता के मंत्रदृष्टा बनकर आते रहे हैं। कोई भी समाज कुरीतियों से मुक्त नहीं है। हर समाज में समय के साथ कुछ गिरावट आती है। मूल बात यह है कि क्या समाज अपनी गिरावट के विरूद्ध तनकर खड़ा होता है या नहीं। उसमें आत्मालोचन और आत्मसमीक्षा की प्रवृत्ति है या नहीं। हिंदु समाज इस अर्थ में खास है कि उसने प्रश्नाकुलता को समाज में मान्यता दी है। वह सती प्रथा, बाल विवाह, छूआछूत, जातीय विद्वेष के विरूद्ध खड़ा हुआ और स्त्री शिक्षा, स्त्री को न्याय, मनुष्य की बराबरी के मानकों को स्वीकार करते हुए एक नया भारत बनाने की ओर है। समाज में 'जातिद्वेष' मान्यता नहीं है।

हम मानते रहे हैं कि जाति का गौरव होना चाहिए किंतु जाति भेद ठीक नहीं। हमारे अनेक ऋषि व्यास, बाल्मीकि, संत रविदास, संत रसखान हमारे श्रद्धास्थान हैं। क्योंकि हमें बताया गया और हमने माना भी कि "जाति-पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।" हमारी परंपरा के सर्वोच्च नायक भगवान श्रीराम के समरसता इन्हीं गुणों से मर्यादा पुरूषोत्तम बने। अपनी उदार भावनाओं से वे 'शबरी के राम' हैं तो 'बाल्मीकि के भी राम' हैं। वे तुलसी के राम हैं तो कबीर के भी राम हैं। वे हनुमान के हृदय में हैं तो आहिल्या के भी उद्धारकर्ता हैं। वे निषादराज के परममित्र हैं, तो किष्किंधानरेश सुग्रीव के भी मित्र हैं। इस परंपरा को समझने वाले ही भारत के मन को समझ सकते हैं।

भारतीय समाज को लांछित करने के लिए उस पर सबसे बड़ा आरोप वर्ण व्यवस्था का है। जबकि वर्ण व्यवस्था एक वृत्ति थी, टेंपरामेंट थी। आपके स्वभाव, मन और इच्छा के अनुसार आप उसमें स्थापित होते थे। व्यावसायिक वृत्ति का व्यक्ति वहां क्षत्रिय बना रहने को मजबूर नहीं था, न ही किसी को अंतिम वर्ण में रहने की मजबूरी थी। अब ये चीजें काल बाह्य हैं। वर्ण व्यवस्था समाप्त है। जाति भी आज रूढ़ि बन गयी किंतु एक समय तक यह हमारे व्यवसाय से संबंधित थी। हमारे परिवार से हमें जातिगत संस्कार मिलते थे- जिनसे हम विशेषज्ञता प्राप्त कर 'जाब गारंटी' भी पाते थे। इसमें सामाजिक सुरक्षा थी और इसका सपोर्ट सिस्टम भी था। बढ़ई, लुहार, सोनार, केवट, माली, निषाद, बुनकर ये जातियां भर नहीं है। इनमें एक व्यावसायिक हुनर और दक्षता जुड़ी थी। गांवों की अर्थव्यवस्था इनके आधार पर चली और मजबूत रही। आज यह सारा कुछ उजड़ चुका है। हुनरमंद जातियां आज रोजगार कार्यालय में रोजगार के लिए पंजीयन करा रही हैं। जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों ही अब अपने मूल स्वरूप में काल बाह्य हो चुके हैं। अप्रासंगिक हो चुके हैं। ऐसे में जाति के गुण के बजाए, जाति की पहचान खास हो गयी है। इसमें भी कुछ गलत नहीं है। हर जाति का अपना इतिहास है, गौरव है और महापुरुष हैं। ऐसे में जाति भी ठीक है, जाति की पहचान भी ठीक है, पर जातिभेद ठीक नहीं है। जाति के आधार भेदभाव यह हमारी संस्कृति नहीं। यह मानवीय भी नहीं और सभ्य समाज के लिए जातिभेद कलंक ही है।

भारत के इतिहास में तमाम ऐसे पृष्ठ हैं, जिसमें हमारी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए समाज के हर वर्ग के लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। विदेशी आक्रामणों से जूझते हुए भी हमारे समाज ने अपनी सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखा। बाद के कालखंड में विभेदकारी शासकों ने भारतीय समाज में विभाजन के बीज बोए क्योंकि उन्हें अपने राज को स्थाई बनाना था। लोगों के हाथ से हुनर छीन कर उन्हें दास बनाना उनका मकसद था। यह काम बिना बंटवारे की राजनीति से संभव नहीं था। भारत के सामने अपनी एकता को बचाने का एक ही मंत्र है, 'सबसे पहले भारत'। इसके साथ ही हमें अपने समाज में जोड़ने के सूत्र खोजने होगें। भारत विरोधी ताकतें तोड़ने के सूत्र खोज रही हैं, हमें जोड़ने के सूत्र खोजने होगें। किन कारणों से हमें साथ रहना है, वे क्या ऐतिहासिक और सामाजिक कारण हैं जिनके कारण भारत का होना जरूरी है। इन सवालों पर सोचना जरूरी है। अगर वे हमारे समाज को तोड़ने, विखंडित करने और जाति, पंथ के नाम पर लड़ाने के लिए सचेतन कोशिशें चला सकते हैं, तो हमें भी इस साजिश को समझकर सामने आना होगा। भारत का भला और बुरा भारत के लोग ही करेगें। इसका भला वे लोग ही करेंगें जिनकी मातृभूमि और पुण्यभूमि भारत है। वैचारिक गुलामी से मुक्त होकर, नई आंखों से दुनिया को देखना। अपने संकटों के हल तलाशना और विश्व मानवता को सुख के सूत्र देना हमारी जिम्मेदारी है।

भारत अपनी लंबी गुलामी से उपजी इसी पीड़ा को आजतक भोग रहा है। कोई भी राष्ट्र इतने लंबे समय की गुलामी के बाद तमाम राष्ट्रों की तरह समाप्त हो जाता, किंतु भारत खड़ा है क्योंकि उसके पास परंपरा का उत्तराधिकार था। ऋषियों और संतों द्वारा दिया गया आध्यात्मिक उत्तराधिकार था। भक्ति ने भारत को हमेशा बचाया और बदला है। हमारी संत परंपरा हमारी जड़ों में एकता और समरसता के सूत्र पिरोती रही है। उनकी शरण में भारत खुद को तलाशता रहा है और सामने खड़े प्रश्नों से मुक्ति पाता रहा है। कुंभ जैसे आयोजन उसके नवपरिष्कार का अवसर देते रहे हैं, तो समाज में प्रवास कर संत शक्ति उसकी शक्ति को संगठित करती रही है। आज समरसता के मंत्रदृष्ठा अनेक सामाजिक संगठन भी सक्रिय होकर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। भारत जाग रहा, अपना पुर्नअविष्कार कर रहा है। अपनी सांस्कृतिक धारा से जुड़कर अपने संकटों के हल तलाश रहा है। यही यात्रा समरसता की वाहक भी और प्रस्थान बिंदु भी। सामाजिक एकता और सामाजिक समरता के बिना हम 'एक भारत और श्रेष्ठ भारत' नहीं बना सकते। इसलिए एकत्व के तत्व खोजना और मनों को जीतना हमारी कोशिश होनी चाहिए। यही बात 'भारत' को 'समर्थ भारत' बनाएगी।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

मध्य प्रदेश सरकार की ईवी पॉलिसी से इंदौर उत्साहित, 31 हजार से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड

परिवहन विशेष न्यूज

राज्य सरकार की ईवी पॉलिसी से इंदौर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आएगी। फिलहाल इंदौर में अब तक 31 हजार से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। प्रदेश में किसी तरह की छूट न होने से ईवी वाहनों की बिक्री अपेक्षाकृत कम हो रही थी। अब प्रदेश की नई ईवी पॉलिसी बनने जा रही है। इसमें सब्सिडी की घोषणा की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात समेत अन्य राज्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इनकी खरीद पर सब्सिडी दे रहे हैं। इससे उन राज्यों में ईवी को बढ़ावा मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश कोई छूट न देकर पीछे रह गया। अब राज्य नई ईवी नीति बनाने जा रही है, जिसमें सब्सिडी की घोषणा होने की संभावना है।

इंदौर का ईवी बाजार और ऑटोमोबाइल उद्योग उत्साहित है। पीथमपुर और सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में ईवी पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां काम कर रही हैं। अब उन्हें उम्मीद है कि नई नीति के बाद इंदौर और पीथमपुर में नई ईवी उत्पादन इकाइयां स्थापित होंगी।

इंदौर में ईवी वाहनों की संख्या 31,000 के पार हो गई है। सड़कों पर 19,000 से ज्यादा ईवी दोपहिया वाहन दौड़ रहे हैं। कारों की बात करें तो इनकी संख्या भी 1,100 के पार हो गई है। ई-रिक्शा 8,000 के करीब हैं। ई-रिक्शा कारों की संख्या 1,525 है। थ्री-व्हीलर सवारियों की संख्या भी 547 के करीब पहुंच गई है। शहर में 70 ई-बसें भी चल रही हैं। मोटर कैब की संख्या भी 40 तक पहुंच गई है।

घाटे के बावजूद ओला के शेयर खरीदने के लिए दौड़ रहे लोग, ये 7 कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और सबकी नजरों से हैं ओझल

परिवहन विशेष न्यूज

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयरों में लिस्टिंग के बाद से काफी उछाल आया है। लिस्टिंग के पहले सात दिनों में शेयर की कीमत ₹76 से बढ़कर ₹157 हो गई थी, लेकिन मंगलवार 20 अगस्त को इसमें करीब 7% की गिरावट देखने को मिली है और यह ₹136 के आसपास कारोबार कर रहा है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में 32% रेवेन्यू उछाल दर्ज किया, जिससे यह ₹1,644 करोड़ हो गया। हालांकि, इसी तिमाही में कंपनी का घाटा भी बढ़कर ₹347 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹267 करोड़ था। घाटे में चल रही कंपनी में निवेश करने के पीछे लोगों के अलग-अलग कारण हैं। इसके उलट कुछ लोग ओला के शेयरों में उछाल को जाल मान रहे हैं और इस शेयर से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक के अलावा ईवी सेक्टर में काम करने वाली और भी कंपनियां हैं।

ओला इलेक्ट्रिक के लिए सबसे बड़ी चुनौती फाइनेंस कॉस्ट में बढ़ोतरी रही है, जो पिछले साल के 36 करोड़ रुपये से बढ़कर 67 करोड़ रुपये हो गई है। इसके साथ ही कंपनी का कुल खर्च भी बढ़ा है, जो पिछले साल के 1,461 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,849 करोड़ रुपये हो गया है। इसके ऊपर से मुनाफे में कमी भी खतरे का संकेत है। इसी आधार पर सोशल मीडिया पर कई इंफ्लूएंसर ओला के शेयरों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि इनमें से कितने सेबी रजिस्टर्ड हैं और कितने सिर्फ झूठे हैं, यह अलग बात है, लेकिन सामने खड़ी सच्चाई इसके आंकड़ों में झलकती है।

ऐसा नहीं है कि ओला इलेक्ट्रिक ही ईवी सेक्टर में काम करने वाली अकेली कंपनी है। कई अन्य कंपनियां भी या तो सीधे इलेक्ट्रिक वाहन बना रही हैं या फिर दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर कंपनी, बजाज ऑटो, सर्वोटेक पावर सिस्टम्स, वार्डविज़ार्ड इनोवेशन एण्ड मोबिलिटी और टनवल ई-मोटर्स लिमिटेड प्रमुख हैं।

(डिसक्लेमर : यह खबर केवल सूचना के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है। अगर आप इनमें से किसी भी शेयर में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले किसी प्रमाणित निवेश सलाहकार से सलाह लें। आपके किसी भी लाभ या हानि के लिए ईवी ड्राइव द फ्यूचर जिम्मेदार नहीं होगा।

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को नहीं मिल रही सब्सिडी, नई नीति का इंतजार

परिवहन विशेष न्यूज

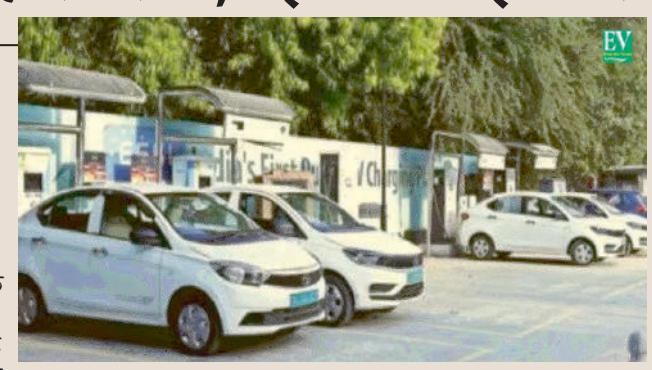

कई महीनों से दिल्ली कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और इस वजह से दिल्ली सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं लटकी हुई हैं। इन्हीं में से एक है दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0, जिसका ड्राफ्ट परिवहन विभाग ने तैयार कर लिया है, लेकिन जब तक कैबिनेट इसे मंजूरी नहीं देती, तब तक नई पॉलिसी को लागू करना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री के जेल से बाहर आने के बाद ही सरकार का कामकाज सुचारू रूप से शुरू हो पाएगा और उसके बाद ही पॉलिसी के ड्राफ्ट पर कैबिनेट के अंदर और बाहर चर्चा होगी और उस पर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और उस आधार पर पॉलिसी में जरूरी सुधार करने के बाद कैबिनेट से पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद ही एलजी भी इसे मंजूरी देंगे। इसके बाद ही पॉलिसी को लागू किया जाएगा।

दिल्ली सरकार की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की डेडलाइन खत्म हो गई है। यह पॉलिसी 7 अगस्त 2020 को तीन साल की अवधि के लिए लागू की गई थी, जिसे पहले 31 दिसंबर 2023 और फिर 30 जून 2024 तक बढ़ाया गया था। नियमों के मुताबिक अब जब तक नई पॉलिसी नहीं आ जाती, पुरानी पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पुरानी पॉलिसी को खत्म हुए करीब डेढ़ महीने बीत चुके हैं और इसका असर अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भी दिखने लगा है।

नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को अब पहले की तरह सरकार की ओर से कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। ऐसे में उन्हें शोरूम कीमत पर ही वाहन खरीदने पड़ रहे हैं। इस वजह से पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में मामूली गिरावट देखी जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल दिल्ली में करीब 74 हजार नए इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, लेकिन इस साल यानी अगस्त 2024 के मध्य तक करीब 46 हजार वाहन ही बिक पाए हैं। इतना ही नहीं पॉलिसी की डेडलाइन यानी जून 2024 से दो से तीन महीने पहले तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को भी अभी तक सब्सिडी की रकम नहीं मिली है।

परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार सब्सिडी के लिए आवेदन करने वाले पोर्टल में किसी तरह की तकनीकी दिक्कत के कारण यह समस्या आई थी, जो अभी भी बनी हुई है। इसके कारण कई लोगों का सब्सिडी भुगतान भी अटका हुआ है, जिसे सरकार सीधे खरीदार के खाते में ट्रांसफर करती है। इसके कारण लोगों का इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के प्रति रुझान भी कुछ हद तक कम हुआ है। पॉलिसी न होने के बावजूद लोग अभी भी इस उम्मीद में सब्सिडी छूट का लाभ लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं कि अगर सरकार कोई नई पॉलिसी लाती है और पहले की तरह बैंक लोन लेकर इसे लागू करती है, तो शायद उन्हें भी सब्सिडी का कुछ लाभ मिले और लोगों का ईवी खरीदने के प्रति रुझान बढ़े।

बीएमडब्ल्यू की चीन निर्मित इलेक्ट्रिक मिनी यात्री कार पर यूरोपीय संघ में टैरिफ घटकर हुआ 21.3%

बीएमडब्ल्यू ने कहा कि चीन में इलेक्ट्रिक मिनी का उत्पादन करने वाले उसके संयुक्त उद्यम को यूरोपीय संघ के चीनी निर्मित ईवी पर शुल्क संबंधी नवीनतम मसौदा टैरिफ दस्तावेज में 'सहयोगी कंपनी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे वह 21.3 प्रतिशत की कम शुल्क दर के लिए पात्र हो गया है।

कार निर्माता ने एक बयान में कहा, 'यह तर्कसंगत है कि स्पॉटलाइट ऑटोमोटिव लिमिटेड यानी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मिनी कारों का उत्पादन करने के लिए चीन में ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ हमारा संयुक्त उद्यम को सहयोगी कंपनियों की श्रेणी में लाया जाए।'

टैरिफ की घोषणा से पहले मिनी ब्रुसेल्स के सैंपल विश्लेषण का हिस्सा नहीं थी, जिसका मतलब है कि वे शुरू में स्वचालित रूप से 37.6 प्रतिशत के उच्चतम टैरिफ स्तर के अधीन थे।

इससे पहले मंगलवार, 20 अगस्त को, यूरोपीय आयोग ने चीन में बनी टेस्ला कारों के आयात पर प्रस्तावित टैरिफ कटौती की घोषणा की। इसने यह भी कहा कि यूरोपीय वाहन निर्माताओं के साथ संयुक्त उपक्रम में शामिल कुछ चीनी कंपनियों को चीन में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रस्तावित दंडात्मक टैरिफ में कमी मिल सकती है।

कथित चीनी सब्सिडी की यूरोपीय संघ की सबसे हाई-प्रोफाइल जांच में, आयोग ने अपनी सब्सिडी-विरोधी जांच का मसौदा जारी किया, जिससे बीजिंग की ओर से जवाबी कार्रवाई की धमकियाँ मिलीं।

इसने टेस्ला के लिए 9 प्रतिशत की नई निचली दर निर्धारित की, जो जुलाई में रिपोर्ट की गई 20.8 प्रतिशत से कम है।

यूरोपीय संघ के कार्यकारी ने मंगलवार, 20 अगस्त को कहा कि उसका अभी भी मानना है कि चीनी ईवी उत्पादन को व्यापक सब्सिडी से लाभ हुआ है और उसने 36.3 प्रतिशत तक का अंतिम टैरिफ प्रस्तावित किया है। यह जुलाई में आयोग द्वारा यूरोपीय संघ की सब्सिडी-विरोधी जांच में सहयोग न करने वाली कंपनियों के लिए निर्धारित 37.6 प्रतिशत के अधिकतम अनंतिम शुल्क से थोड़ा कम है।

देश के 85 प्रतिशत से अधिक ईवी स्टेशन कर्नाटक में

परिवहन विशेष न्यूज

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) के अनुसार, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 5,765 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हैं, जिनमें से लगभग 85% यानी 4,462 स्टेशन बेंगलुरु के शहरी जिले में हैं। बीईई डेटा से पता चलता है कि कर्नाटक इस सूची में सबसे आगे है, उसके बाद महाराष्ट्र में 3,728 स्टेशन, उत्तर प्रदेश में 1,989 स्टेशन और दिल्ली में 1,941 स्टेशन हैं।

ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज ने कहा कि कर्नाटक ने 5,765 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ देश में एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। यह उपलब्धि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की मजबूत प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। राज्य की ओर से लागू की गई रणनीतिक पहल और नीतियां एक मजबूत ईवी बुनियादी ढांचा बनाने और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस प्रयास को दर्शाती हैं।

ईवी चार्जिंग स्टेशनों को विभिन्न स्रोतों से शुरू किया जाएगा जैसे कि केंद्र सरकार की हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण, बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (सकॉम) का निवेश और राज्य परिवहन विभाग से ग्रीन सेस फंड और राज्य परिवहन विभाग से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) को वित्त पोषित किया गया है।

इस साल की शुरुआत में राज्य बजट 2024 में सरकार ने पीपीपी मॉडल के माध्यम से राज्य भर में 2,500 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की थी। सरकार बिजली आपूर्ति कंपनियों (एसकॉम) के सहयोग से 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 35 करोड़ रुपये का निवेश करने की भी योजना बना रही है।

ईवी टैक्स क्रेडिट को किया जा सकता हैं खत्म, सलाहकार के रूप में मस्क की जरूरत : डोनाल्ड ट्रंप

परिवहन विशेष न्यूज

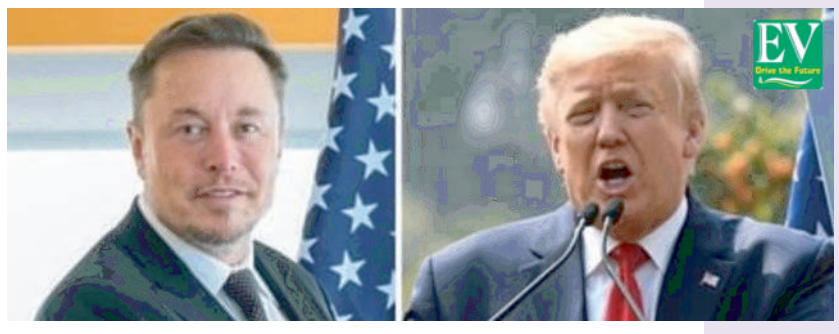

रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार, 19 अगस्त को कहा कि अगर वे चुने जाते हैं तो वे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 7,500 डॉलर के टैक्स क्रेडिट को खत्म करने पर विचार करेंगे, साथ ही उन्होंने कहा कि वे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को कैबिनेट या सलाहकार की भूमिका के लिए नामित करने के लिए तैयार हैं।

पेंसिल्वेनिया के यॉर्क में एक अभियान कार्यक्रम के बाद मीडिया को दिए साक्षात्कार में जब ट्रम्प से ईवी क्रेडिट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'कर क्रेडिट और कर प्रोत्साहन सामान्य रूप से अच्छी चीज नहीं हैं।'

यह पूछे जाने पर कि क्या वे मस्क को सलाहकार की भूमिका या कैबिनेट की नौकरी में नामित करने पर विचार करेंगे, ट्रंप ने कहा कि वे ऐसा करेंगे। ट्रंप ने कहा, 'वे बहुत होशियार आदमी हैं। मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा, अगर वे ऐसा करेंगे, तो मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। वह एक शानदार व्यक्ति हैं।'

मस्क ने पिछले महीने सार्वजनिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में ट्रंप का समर्थन किया था। टेस्ला ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

अगर ट्रंप निर्वाचित होते हैं, तो वे ट्रेजरी विभाग के नियमों को उलटने के लिए कदम उठा सकते हैं। इन नियमों से वाहन निर्माताओं के लिए 7,500 डॉलर क्रेडिट का लाभ उठाना आसान हो गया है या वे यूएस कांग्रेस से इसे पूरी तरह से निरस्त करने के लिए कह सकते हैं। राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने ईवी टैक्स क्रेडिट को निरस्त करने की मांग की, जिसे बाद में 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा विस्तारित किया गया।

ईवी टैक्स क्रेडिट के बारे में ट्रंप ने कहा, ₹मैं इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रिक कारों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, लेकिन मैं गैसोलीन से चलने वाली कारों का भी प्रशंसक हूं और हाइब्रिड और जो कुछ भी आता है, उसका भी।₹

उन्होंने कहा कि वे बाइडन प्रशासन के नियमों को रद्द कर देंगे, जो वाहन निर्माताओं को सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करने के लिए ज्यादा ईवी और प्लग-इन हाइब्रिड बनाने के लिए प्रेरित करेंगे और उन्होंने कहा कि उन्हें लागत और बैटरी रेंज के मुद्दों के कारण ईवी के लिए 'बहुत छोटा बाजार' दिखाई देता है।

ट्रंप ने यह भी कहा कि वे नए टैरिफ लगाकर मेक्सिको से डेट्रायट के तीन बड़े वाहन निर्माताओं यानी श्री ऑटोमेकर्स और अन्य द्वारा उत्पादित वाहनों के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए कदम उठाएंगे और चीनी ऑटोमेकर्स को अमेरिकी बाजार के वाहनों के लिए मेक्सिको में नए प्लांट बनाने से रोकेंगे। जब वे राष्ट्रपति थे उस दौरान भी उन्होंने इसी तरह की धमकियां दी थीं।

ट्रंप ने कहा, 'अगर आप उन कारों पर टैरिफ लगाते हैं, तो वे यहां बनेंगी। यह बहुत सरल है। यह जटिल नहीं है। यदि आप मेक्सिको से कहते हैं, 'देखो, तुम हमारे कार उद्योग को चुरा रहे हो,' जो वे अभी कर रहे हैं।'

लेकिन ट्रंप चीनी और अन्य ऑटोमेकर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में वाहन बनाने के लिए खुले हैं। ट्रंप ने कहा, 'हम प्रोत्साहन देने जा रहे हैं और अगर चीन और अन्य देश यहां आकर कारें बेचना चाहते हैं, तो वे यहां प्लांट बनाने जा रहे हैं, और वे हमारे श्रमिकों को काम पर रखने जा रहे हैं।' 'हम अपनी कारें खुद बनाएंगे। मैं अपनी कारें खुद बनाना चाहता हूं।'

अन्य खबरों से ट्रंप ने अल्फाबेट के गूगल की कड़ी आलोचना की, लेकिन यह कहने से इनकार कर दिया कि क्या उन्हें लगता है कि इस प्रौद्योगिकी कंपनी को तोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस महीने एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया था कि गूगल एक अवैध एकाधिकार है।

ट्रंप ने गूगल के बारे में कहा, ₹वे लगभग वाइल्ड वेस्ट की तरह हैं।₹ लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें किस तरह की सजा का सामना करना चाहिए। साथ ही कहा, 'उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।'

ट्रंप ने पहले कहा था कि वे शॉर्ट वीडियो एप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगने से रोकेंगे। अप्रैल में एक कानून को मंजूरी दी गई थी, जिसमें चीनी मालिक बाइटडांस के लिए टिकटॉक की अमेरिकी संपत्ति को बेचने के लिए 19 जनवरी, 2025 की समय सीमा तय की गई थी। यह पूछे जाने पर कि क्या वे टिकटॉक पर चीनी स्वामित्व को जारी रखना स्वीकार कर सकते हैं। ट्रंप ने सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि बाइटडांस इसे बेच सकता है।

ट्रंप ने कहा, 'इस तरह की किसी चीज पर प्रतिबंध लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। आप इस समीकरण में कई अलग-अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन टिकटॉक ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है।'

सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों से सामान भेजेगी आइकिया

होम फर्नीचर सेक्टर की दिग्गज स्वीडिश कंपनी आइकिया ने कहा है कि वह साल 2025 तक भारत में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए ही डिलीवरी का कारोबार करेगी। 2018 में भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाली कंपनी ने सिकंदराबाद, बेंगलुरु और पुणे में ईवी के जरिए अपने अप्लायंसेज लॉन्च किए हैं। वहां उसकी पूरी डिलीवरी ईवी के जरिए ही होती है।

वर्तमान में भारत में आइकिया की 88 प्रतिशत डिलीवरी इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से की जाती है। आज, बुधवार, 21 अगस्त को जारी एक बयान में कंपनी ने कहा कि उसने हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई और गुजरात में लगभग 100 ईवी तैनात किए हैं।

आइकिया इंडिया की कंट्री कस्टमर फुलफिलमेंट मैनेजर साइबा सूरी ने बताया, ₹इन इलेक्ट्रिक वाहनों की मदद से हम जुलाई 2024 तक देशभर में ग्राहकों तक 90 फीसदी से ज्यादा सामान बिना किसी उत्सर्जन यानी प्रदूषण के पहुंचा रहे हैं।₹

कंपनी ने पहली बार 2019 में इलेक्ट्रिक वाहन डिलीवर करना शुरू किया। वैश्विक स्तर पर, आइकिया का लक्ष्य जलवायु के प्रति जागरूक कंपनी बनना है। इसका लक्ष्य 2030 तक पूरे मूल्य श्रृंखला में ग्रीनहाउस उत्सर्जन को आधा करना और 2050 तक नेट जीरो तक पहुंचना है।

आइकिया अगले साल दिल्ली-एनसीआर में भी परिचालन शुरू करने की योजना बना रही है, जहाँ शुरू से ही इलेक्ट्रिक वाहनों की डिलीवरी की जाएगी। आइकिया हैदराबाद में भी उसी दिन डिलीवरी शुरू कर रही है और आने वाले साल में अपने सभी बाज़ारों में विस्तार करने की योजना बना रही है।

शिक्षा जगत के लिए चुनौतियां

डा. वरिंद्र भाटिया

आजादी के वक्त देश में सिर्फ 20 यूनिवर्सिटीज और 404 कॉलेज थे। आज इनकी संख्या में कई गुना इजाफा हो चुका है। अतीत में हायर एजुकेशन में क्वांटिटी पर ज्यादा और क्वालिटी पर फोकस कम रहा है। आज भी थोक के भाव से यूनिवर्सिटीज खुली हैं, मगर पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थिति और भी बुरी है। निजी संस्थाओं और उद्यमियों ने कॉलेज तो खोल दिए हैं, मगर कई जगह फैकल्टी अच्छी नहीं रखी जा रही है।

आजादी के बाद अब तक बनी सरकारें जानती थी कि हायर एजुकेशन पर फोकस किए बिना ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में झंडे नहीं गाड़े जा सकते। इस पर भी बहुत काम हुआ है। आजादी के वक्त देश में सिर्फ 20 यूनिवर्सिटीज और 404 कॉलेज थे। आज इनकी संख्या में कई गुना इजाफा हो चुका है। अतीत में हायर एजुकेशन में क्वांटिटी पर ज्यादा और क्वालिटी पर फोकस कम रहा है। आज भी थोक के भाव से यूनिवर्सिटीज खुली हैं, मगर पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थिति और भी बुरी है। निजी संस्थाओं और उद्यमियों ने कॉलेज तो खोल दिए हैं, मगर कई जगह फैकल्टी अच्छी नहीं रखी जा रही है। कई संस्थानों में अच्छी लैब्स भी नहीं हैं। स्कूली शिक्षा में कई जगह निजी क्षेत्र ने अच्छा काम किया है, मगर हायर एजुकेशन में अभी बहुत काम होना बाकी है'

एक बार फिर हमने आजादी की सालगिरह मनाई। आजादी के बाद शिक्षा, खास तौर पर उच्च शिक्षा को लेकर हम कहां खड़े हैं, यह विचारना जरूरी है। शिक्षा राष्ट्र की समृद्धि का एकमात्र जरिया है। शिक्षा वो सूत्र है, जिसे देश के आजाद होते ही लीडरशिप ने समझ लिया और इस पर काम किया। आजादी के वक्त देश की आबादी 36 करोड़ थी, मगर साक्षरता सिर्फ 18 परसेंट। वहीं, महिलाओं के मामले में हालात और खराब थे। देश की आजादी के समय 9 परसेंट से भी कम महिलाएं पढ़ी-लिखी थीं। यानी 11 में से सिर्फ एक महिला पढ़-लिख सकती थी। आजादी के वक्त देश में सिर्फ डेढ़ लाख स्कूल थे, आज देश में स्कूलों की संख्या बढ़कर बीस लाख से ज्यादा हो गई है। इन स्कूलों में करीब 24 करोड़ छात्र पढ़ते हैं। स्कूली शिक्षा में सरकार और निजी क्षेत्र ने भी बहुत निवेश किया है। हालांकि इन दिनों कई कारणों से देश के अनेक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और हर व्यक्ति अपने सामथ्र्य के हिसाब से अपने बच्चों को पब्लिक यानी निजी स्कूलों में पढ़ाना चाहता है। चिंता की बात यह भी है कि नई शिक्षा नीति में खास तौर से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार के प्रावधान की बातें बहुत हो रही हैं, लुभावनी योजनाएं बन रही हैं, लेकिन इसको लागू करने में अड़चनों को तुरंत दूर किया जाना जरूरी होगा। यह भी हो सकता है कि साधनों के अभाव एवं दक्ष-प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण हम नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं। बेहतर हो कि नई शिक्षा नीति के जरिए मियारी स्कूली शिक्षा देने का हमारा लक्ष्य भटकना नहीं चाहिए।

जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, तो उच्च शिक्षा हर क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के रास्ते खोलती है। आजादी के बाद अब तक बनी सरकारें जानती थी कि हायर एजुकेशन पर फोकस किए बिना ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में झंडे नहीं गाड़े जा सकते।

इस पर भी बहुत काम हुआ है। आजादी के वक्त देश में सिर्फ 20 यूनिवर्सिटीज और 404 कॉलेज थे। आज इनकी संख्या में कई गुना इजाफा हो चुका है। अतीत में हायर एजुकेशन में क्वांटिटी पर ज्यादा और क्वालिटी पर फोकस कम रहा है। आज भी थोक के भाव से यूनिवर्सिटीज खुली हैं, मगर पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थिति और भी बुरी है। निजी संस्थाओं और उद्यमियों ने कॉलेज तो खोल दिए हैं, मगर कई जगह फैकल्टी अच्छी नहीं रखी जा रही है। कई संस्थानों में अच्छी लैब्स भी नहीं हैं। आज हमारे सामने सैकड़ों निजी इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे भी हैं जहां फीस निजी स्कूलों से कम है। हालांकि स्कूली शिक्षा में कई जगह निजी क्षेत्र ने अच्छा काम किया है, मगर हायर एजुकेशन में अभी बहुत काम होना बाकी है। वर्तमान में हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, जो धीरे-धीरे ग्लोबल व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। इस समय सभी शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी ज्यादा है, जिन्हें इस दिशा में अभी काफी काम करना है। शिक्षण संस्थाओं के प्रसार की दिशा में भले ही हम प्रगति कर रहे हों, लेकिन यह साफ है कि शिक्षा डिजिटल तकनीक माध्यम से देने में हम असफल रहे हैं। आने वाले समय में विकसित भारत को निर्मित करने का मुख्य आधार शिक्षा ही है। इसके लिए हमें आधुनिक शिक्षा एवं शिक्षकों को समग्र दृष्टि से परिपक्व बनाना होगा, तभी शिक्षा की कमियां दूर हो सकेंगी। हमें अपने छात्रों को सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है। हमें यह देखना होगा कि देश के छात्र दुनिया में कहीं भी काम करने के योग्य हों। यह कैसे संभव हो सकेगा? इस बार की आजादी की इस वर्षगांठ पर हमारा शिक्षा जगत और सरकारें इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें। शिक्षा में गुणवत्ता का होना जरूरी है। इसके लिए हमें शिक्षकों को अध्यापन से इतर कार्यों से विमुक्त करना होगा। अभी तक अध्यापकों की ड्यूटी चुनावी कार्यक्रमों के निपटान, मिड डे मील का प्रबंधन, सर्वेक्षण कार्यों तथा कई और सरकारी कार्यों के निपटान में लगाई जा रही हैं। इससे अध्यापकों के समक्ष यह संकट उत्पन्न हो जाता है कि सिलेबस का अध्यापन पूरी तरह कैसे करवाया जाए। वैसे शिक्षा केवल सिलेबस के अध्यापन तक सीमित विषय नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य छात्र को इस काबिल बनाना है कि वह अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए आजीविका का प्रबंध कर सके, और साथ में शिक्षा का मतलब यह भी है कि इसे ग्रहण करने के बाद शिक्षार्थी सच को सच तथा झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत दिखा सके। शिक्षा का लक्ष्य छात्र को एक कंपलीट पर्सन बनाना होता है। छात्र का नैतिक कल्याण और उसमें मानवीय सद्गुणों का प्रत्यारोपण भी शिक्षा का लक्ष्य है।

इस काम को छात्रों, अभिभावकों तथा अध्यापकों के आपसी सहयोग से पूरा किया जा सकता है। सद्गुण संपन्न नागरिक बनाना ही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा जगत के लिए एक चुनौती यह भी है कि निजी शिक्षण संस्थानों की उपयोगिता को स्वीकार तो किया जाए, लेकिन इनके कारण शिक्षा इतनी महंगी न हो जाए कि आम छात्र, गरीब छात्र तक इसकी पहुंच ही न हो। महंगी शिक्षा के कारण गरीब छात्रों का शिक्षा से वंचित रह जाना भारतीय शिक्षा जगत की एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा का बढ़ता व्यापारीकरण एक बड़ी चुनौती है। इस विषय पर व्यापक चिंतन की जरूरत है, ताकि शिक्षा गरीब छात्र तक भी सुलभ रहे। ऐसा भी देखने में आता है कि निजी शिक्षण संस्थान छात्रों के अभिभावकों से भारी फीस व डोनेशन आदि वसूल करते हैं। निजी स्कूल छात्रों को महंगे दामों पर शिक्षण सामग्री व वर्दी आदि भी बेचते हैं। कापियों, पेंसिल व अन्य शिक्षण सामग्री के नाम पर भारी वसूली होती है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। आज गरीब से गरीब परिवार तक, सभी अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों में शिक्षा दिलाना चाहते हैं, लेकिन इन स्कूलों के भारी-भरकम खर्चों को देखते हुए कई बार गरीब अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल नहीं करवा पाते हैं। शिक्षा जगत की एक चुनौती यह भी है कि सरकारों के शिक्षा पर व्यापक खर्च के बावजूद सरकारी स्कूलों में दाखिल होने वाले छात्रों की संख्या निरंतर घट रही है, जिसके परिणामस्वरूप प्रचलन यह बनता जा रहा है कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को या तो बंद किया जा रहा है, अथवा उन्हें अन्य स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को पर्याप्त वेतन भी मिलता है, लेकिन इसके बावजूद इन स्कूलों के वार्षिक परिणाम उत्साहजनक नहीं हैं। ऐसी ही कई अन्य चुनौतियां भारतीय शिक्षा जगत के सामने हैं, जिनका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। ये चुनौतियां ऐसी नहीं हैं कि समाधान न हो सके, बस, प्रयासों की जरूरत है।

संपादकीय

आर्थिक डेस्टिनेशन-4

उत्तर भारत के पर्यटन मंत्रियों की बैठक में हिमाचल का पक्ष, एक सूत्रधार की भूमिका में काम करे तो क्षेत्रीय सहयोग के कई सेतु सृदृढ़ हो सकते हैं। दिल्ली से जुड़े तमाम राज्य अपनी विविधता, ऐतिहासिकता, भौगोलिक और अन्य कारणों से राष्ट्रीय पर्यटन की कई मंजिलें पैदा करते हैं। पर्यटक यात्राओं के अनुभव एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य के प्रवेश को संभव बना देते हैं। हम आर्थिक, व्यापारिक व रोजगार कारणों से भी एक-दूसरे से जुड़ाव रखते हैं, लेकिन एक-दूसरे के पूरक होने के रास्ते नहीं चुनते। पर्यटन एक स्वाभाविक सेतु है जो इन राज्यों को कतारबद्ध कर देता है। जयपुर तक पहुंचा देशी-विदेशी पर्यटक अक्सर आगे के नक्शे पर हिमाचल देखता है, तो उसे अटल टनल, महामहिम दलाईलामा का प्रवास या बर्फ से लकदक पहाड़ आकर्षित करते हैं। वह धार्मिक यात्रा पर निकल कर हरिद्वार, केदारनाथ से आगे हिमाचल के देवी दर्शन करता हुआ वैष्णो देवी निकल जाना चाहता है। वह उत्तर भारत के चाय बागानों की महक के लिए कांगड़ा घाटी पहुंच जाता है, तो सिख पर्यटन की यात्रा में गोल्डन टैम्पल के साथ पांवटा साहिब, ऊना और मणिकर्ण पहुंच जाता है। ऐसे में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल अगर अपनी पर्यटक योजनाओं में साझापन लाएं तो राष्ट्रीय आर्थिकी का प्रसार होगा। आनंदपुर साहिब से नयनादेवी तक रज्जु मार्ग, प्रमुख पर्यटक स्थलों से हवाई कनेक्टिविटी तथा वंदे भारत से अंब-अंदौरा एवं पठानकोट का सफर जोडक़र करिश्मा हो सकता है। उत्तर भारतीय राज्यों को पर्यटन सर्किट की विरासत खड़ी करके एक-दूसरे को भविष्य के यात्रा वृतांत से जोडऩा होगा। एक क्षेत्रीय विमानन सेवा के तहत हिमाचल के छोटे हवाई अड्डे भी विभिन्न राज्यों से जुड़ सकते हैं। बहरहाल हिमाचल की सुक्खू सरकार पर्यटन राजधानी की अवधारणा में कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार कर रही है।

एक पहाड़ी प्रदेश जहां सरकारी इमारतों के लिए छोटी सी जमीन की उपलब्धता भी टेढ़ी खीर बन जाती है, वहां सुक्खू सरकार ने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए 122 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को धारा 19 की अधिसूचना जारी करने का रास्ता अख्तियार किया है। यहां पुनर्वास का एक ऐसा मॉडल भी तैयार हुआ है जो राज्य के आर्थिक विकास की तासीर बदल सकता है। निस्संदेह कनेक्टिविटी के दरवाजे पर कांगड़ा एयरपोर्ट का बड़ा स्वरूप पूरे हिमाचल के पर्यटन की सदी बदल सकता है, बशर्ते राज्य अपने उस आकर्षण को सहेज सके जो इसकी मौलिकता, पारंपरिक सादगी, सामाजिक शिष्टाचार और भौगोलिक आकर्षण में समाहित है। यानी पर्यटन के पांव के नीचे हमारे खूबसूरत अंदाज न दब जाएं। इससे शायद ही फर्क पड़ेगा कि डेढ़ करोड़ सैलानी आएं या पांच करोड़ आने लगें, लेकिन कोई कितनी बार सुकून के लिए आने लगा और कितने दिन रुकने के लिए बाध्य हो सका, इससे अंतर जरूर आएगा। वैसे एक करोड़ क्षमतावान हाई एंड टूरिस्ट अगर साल में सात दिन रुकें तो सात करोड़ पर्यटकों की क्षमता में आर्थिकी कहीं ज्यादा विकसित होगी। हमें पर्यटकों की शुमारी के बजाय पर्यटक दिवस बढ़ाने की तैयारी करनी होगी। एक नया ट्रेंड हिमाचल में 'पर्यटक दिन' खोजता हुआ किसी आगंतुक को छह-छह महीने तक रोक रहा है। ऐसे पर्यटक गांव-देहात, कैंपिंग साइट्स या होम स्टे को प्राथमिक बना रहे हैं। ऐसे में हमें पर्यटक गांव की अवधारणा में हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक 'पर्यटक गांव' विकसित करना होगा। इस तरह सुक्खू सरकार अगले कुछ सालों में 68 पर्यटक गांव या न्यू डेस्टिनेशन बना सकती है। इसके लिए कोई अतिरिक्त बजट की जरूरत नहीं, बल्कि विभिन्न विभागीय परियोजनाओं से गांव की हस्ती को पर्यटक गांव में तबदील किया जा सकता है। कहीं गांव का धार्मिक स्थल, कहीं जलशक्ति विभाग की सिंचाई परियोजना, कहीं विद्युत परियोजना, कहीं हाट बाजार, कहीं किसी जंगल का नजारा, कहीं लोक कला केंद्र, कहीं बांध परियोजना, कहीं फूलों की खेती या ट्यूलिप गार्डन, कहीं चाय-सेब के बागान, कहीं योग व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, कहीं जनजातीय जीवन, तो कहीं हाईवे पर व्यापार व ऑटो सुविधाएं 68 पर्यटक गांवों की आर्थिकी को नया स्वरूप दे सकती हैं।

राय

किसानी, बेरोजगारी का चुनाव

हरियाणा में किसान और बेरोजगारी निर्णायक चुनावी मुद्दे साबित हो सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की हरियाणा ईकाई ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग, जो एमएसपी तय करता है, किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 736 किसानों के स्मारक की मांग और अन्य जुड़े मामलों पर विमर्श करना तय किया है। ये कोई मान्यता प्राप्त किसान संगठन नहीं हैं। केंद्र और राज्य सरकार अपने स्तर पर एमएसपी को लेकर लगातार विमर्श करती रही हैं। यह दीगर है कि फिलहाल कोई भी निष्कर्ष सामने नहीं है। अब किसानों के विमर्श का निष्कर्ष कुछ भी रहे, लेकिन यह हरियाणा के विधानसभा चुनाव की दशा-दिशा तय कर सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में कुरुक्षेत्र में रैली को संबोधित किया था, जिसमें एमएसपी को लेकर गारंटी दी गई थी कि सरकार एमएसपी पर ही फसलें खरीदेगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने उस गारंटी को खारिज कर दिया। किसान राष्ट्रीय स्तर पर एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं, लिहाजा केंद्रीय मंत्रियों से ही बातचीत होती रही है। केंद्र सरकार ने ही एक कमेटी बनाई थी, जिसके फैसले अभी सार्वजनिक किए जाने हैं। हरियाणा की फसलों की खरीद सीमित है तथा हरियाणा के किसानों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री की गारंटी को 'चुनावी स्टंट' करार दिया है। किसानों का दावा है कि मुख्यमंत्री सैनी के घोषित नए एमएसपी से उन्हें 3851 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। नुकसान का यह आंकड़ा किस आधार पर तय किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि किसान आंदोलन में हरियाणा अपेक्षाकृत सक्रिय नहीं था और न ही आंदोलन के बाद किसान नेताओं को कोई राजनीतिक सफलता मिली। पंजाब और हरियाणा में जिन किसान नेताओं ने चुनाव लड़े, वे पराजित हुए और जमानतें भी जब्त हुईं।

हरियाणा में सबसे अधिक करीब 24 फीसदी आबादी जाटों की है। वे ही अधिकतर किसानी से जुड़े हैं। उनका समर्थन भाजपा, कांग्रेस, इंनेलो, जेजेपी आदि दलों के लिए विभाजित है। सत्ता-विरोधी लहर होने के बावजूद भाजपा 5 लोकसभा सीटों पर जीती और 5 सीटें कांग्रेस के हिस्से आईं। अब भी यही सीधा मुकाबला रहना है, क्योंकि अन्य दल बहुत कमजोर हो चुके हैं अथवा टूट-फूट कर बिखर चुके हैं। फिर भी यह चुनाव आसान नहीं होगा। हरियाणा में भाजपा सरकार और पार्टी के खिलाफ जबरदस्त लहर है। यह लहर पार्टी के भीतर भी महसूस की जा सकती है। भाजपा नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव से पूर्व ही इसे पढ़ लिया था, लिहाजा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा कर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। वह 12 मार्च, 2024 से मुख्यमंत्री हैं। नायब सैनी ने 'नॉन स्टॉप' बैनर से अपनी सरकार का अभियान शुरू किया। अखबारों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापन छपवाए गए और दावे किए गए कि हरियाणा हर क्षेत्र में अब 'नॉन स्टॉप' है। एमएसपी का जिक्र भी किया गया। उसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेसी धड़े ने चुनौती दी, जिसका नारा है-'हरियाणा मांगे हिसाब।' कांग्रेस में शैलजा के नेतृत्व वाला भी धड़ा है और आलाकमान इस धड़ेबाजी को खत्म नहीं कर पाया है। हालांकि बेरोजगारी, किसान-संकट और रुकी, स्थिर, गतिहीन अर्थव्यवस्था आदि मुद्दे हरियाणा में अच्छी तरह परिचित रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के आते-आते विपक्ष ने उन्हें गरमा दिया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डाटा के अनुसार, हरियाणा में बेरोजगारी दर सर्वाधिक है, जबकि सरकार का डाटा इसके बिल्कुल उलट है और वह बेरोजगारी के मामले में हरियाणा को चौथे स्थान पर मानती है। राज्य की औद्योगिक गतिविधियां सीमित हैं व रोजगार प्रभावित है।

बांग्लादेश को ताकत का एहसास कराए भारत

प्रताप सिंह पटियाल

भारत के पड़ोसी मुल्कों तथा कई अन्य देशों में विदेशी खूफिया एजेंसियां भारत विरोधी ताकतों की हिमायत कर रही हैं। अतः विश्व की चौथी ताकतवर सैन्यशक्ति की हैसियत रखने वाले भारत को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। देश के सियासी नेतृत्व को आगामी नीति पर विचार करना चाहिए

सन-1971 की जंग में पाकिस्तान की मदद के लिए एडमिरल 'जॉन मेकेन' के नेतृत्व में आया अमरीका का सातवां एटमी जंगी बेड़ा 'यूएसएस एंटरप्राइज' बंगाल की खाड़ी में तथा ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर 'एचएमएस ईग्ल' अरब सागर में ही खड़े रह गए, लेकिन विश्व की सर्वोत्तम भारतीय थलसेना ने 16 दिसंबर 1971 को ढाका के 'रामना रेसकोर्स गार्डन' में पाक सेना को घुटनों के बल बिठाकर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेआबरू कर दिया था। हिमाचल प्रदेश के कैप्टन 'जतिंदर नाथ सूद' के नेतृत्व में 'पांचवीं गोरखा' रेजिमेंट के जवानों ने बांग्लादेश के महाज पर आठ दिसंबर 1971 को 'पीरगंज' में हमला करके पाक सेना की किलेबंदी को ध्वस्त करके भारत की जीत का एक सुनहरा शिलालेख लिख दिया था। पीरगंज के युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन जतिंदर नाथ सूद को सेना ने 'वीर चक्र' (मरणोपरांत) से नवाजा था। बेशक बांग्लादेश भारतीय सैन्य पराक्रम के रहमो करम से आजाद हुआ था। लेकिन काबिलेगौर रहे कि बांग्लादेश के सैन्य अफसरों की फौजी तालीम सन-1971 तक पाकिस्तान में ही हुई थी। इसीलिए बांग्लादेश की सेना तथा मजहबी जमातें जज्बाती तौर पर पाकिस्तान से आजाद नहीं हुई हैं। अतः बांग्लादेश को भारत विरोधी मानसिकता विरासत में मिली है।

इस्कंदर अली मिर्जा, अयूब खान, याहिया खान, टिक्का खान व जिया उल हक जैसे पाकिस्तान के नामुराद जरनैलों से मिले जम्हूरियत को कुचलने वाले संस्कारों को बांग्लादेश की सेना ने भी पूरी अकीदत से तसलीम कर लिया था, जिसका पहला परिणाम सन-1975 में ही सामने आ गया था। सन-1971 में मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व करने वाले बांग्लादेश के संस्थापक व राष्ट्रपति बंगबंधु 'शेख मुजीबुर रहमान' को बांग्लादेश की सेना ने 15 अगस्त 1975 के दिन उनके परिवार के कई सदस्यों सहित हलाक करके तख्तापलट कर दिया था। पाकिस्तान की तर्ज पर बांग्लादेश में तख्तापलट व तशद्दुद का जो दौर सन-1975 में शुरू हुआ था, वो मौजूदा वक्त तक जारी है। शेख मुजीबुर रहमान की हलाकत व तख्तापलट की साजिश में मुल्लविश 'खोडांकर मुस्ताक अहमद' बांग्लादेश के सदर बने मगर मात्र तीन महीने बाद ही सेना ने तख्तापलट कर दिया था। नवंबर 1975 को राष्ट्रपति बने 'अबू सादात मोहम्मद सईम' को डेढ़ वर्ष बाद ही इस्तीफा देना पड़ा था। शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के एक अन्य अहम किरदार व साबिक वजीरे आजम खालिदा जिया के शौहर जनरल 'जियाउर रहमान' सन-1977 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति पद पर काबिज हो गए। पाक सेना में मेजर रहे जियाउर रहमान ने सन-1965 की जंग में खेमकरण सेक्टर में भारत के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया था तथा पाक सेना ने जिया को 'सितारा-ए-जुर्रत' से नवाजा था। सन-1971 में जियाउर रहमान ने मुक्ति वाहिनी के सेक्टर कमांडर के तौर पर बांग्लादेश की आजादी में भी अपना किरदार अदा किया था तथा जंग के दौरान अपने कमान अधिकारी 'ईस्ट बंगाल रेजिमेंट' के पाक कर्नल 'जंजुआ' का कत्ल करके चटगांव के 'कलुरघाट' रेडियो स्टेशन से 27 मार्च 1971 को बांग्लादेश की आजादी की घोषणा कर दी थी। बांग्लादेश ने जिया को अपने सैन्य एजाज 'बीर उत्तम' से नवाजा था।

लेकिन बांग्लादेश की सेना ने 30 मई 1981 के दिन अपने राष्ट्रपति व सिपाहसालार जियाउर रहमान का कत्ल करके तख्तापलट के मजमून को फिर दोहरा दिया था। भारत की मुखाल्फत करने वाले सियासी दल 'बीएनपी' की स्थापना जियाउर रहमान ने ही की थी। भारत व भूटान दोनों देशों ने छह दिसंबर 1971 को जंग के दौरान ही बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की तथा अन्य मुल्कों से भी बांग्लादेश को मान्यता देने की अपील की थी। लेकिन सन-1980 के दौर में बांग्लादेश के वजीरे आजम रहे 'शाह अजीजुर रहमान' ने 1971 की जंग में पाक सेना का पूरा सहयोग किया था तथा बांग्लादेश में भारतीय सैन्य कार्रवाई का विरोध 'यूएनओ' के मंच पर जाकर किया था। 'रविंद्र नाथ टैगोर' द्वारा लिखित बांग्लादेश के कौमी तराना 'आमार सोनार बांग्ला' को हटाने की आवाज भी शाह अजीजुर रहमान ने ही बुलंद की थी। मगर बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख 'हुसैन मोहम्मद इरशाद' ने सन-1982 में तख्तापलट को अंजाम देकर प्रधानमंत्री अजीजुर रहमान को सत्ता से बेदखल कर दिया था। सन-1971 के युद्ध में

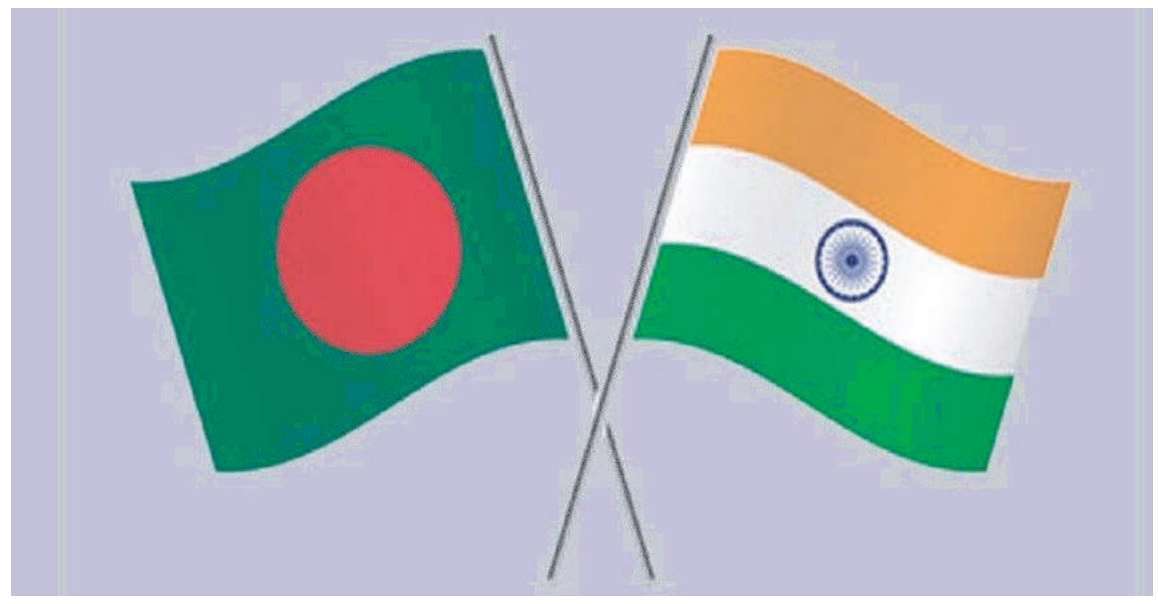

जिल्लतभरी शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए पाक खूफिया एजेंसी 'आईएसआई' ने बांग्लादेश की धरती पर चरमपंथ व कट्टरवाद की पैरवी करने वाली मजहबी जमातों की परवरिश शुरू कर दी थी। हजारों भारतीय सैनिकों की कुर्बानियों के बाद वजूद में आए बांग्लादेश में मौजूद पाक परस्त मजहबी जमातों व कई सियासी रहनुमाओं के जहन में भारत विरोध की चिंगारी एक मुद्दत से सुलग रही है, जिसका एक पहलू मजहब से जुड़ा है।

अलबत्ता यदि भारत की समर्थक रही वजीरे आजम शेख हसीना का तख्तापलट हुआ है तो कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए। मौजूदा हालात इस कदर बद्तर हो चुके हैं कि हिंसक प्रदर्शनकारियों ने मेहरपुर के 'मुजीबनगर' में स्थित 1971 की जंग से जुड़े भारतीय सेना के 'राष्ट्रीय स्मारक' को भी तोड़ डाला है। चरमपंथी जमातों ने पाक सेना के शर्मनाक आत्मसमर्पण तथा भारतीय सेना की शूरवीरता के उन प्रतीकों को नष्ट कर दिया जिनकी कुर्बानियों की बुनियाद पर बांग्लादेश वजूद में आया था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तथा कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदाय के दर्द का वही अफसाना, वही आंसू, तशद्दुद के दौर में खौफ के साए में जीने को मजबूर लोगों के हकूक पर कोई चर्चा नहीं होती। दहशतगर्दी व मजहबी जमातों के निशाने पर रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बहरहाल भारत के पड़ोसी मुल्कों तथा कई अन्य देशों में विदेशी खूफिया एजेंसियां भारत विरोधी ताकतों की हिमायत कर रही हैं। अतः विश्व की चौथी ताकतवर सैन्यशक्ति की हैसियत रखने वाले भारत को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। देश के सियासी नेतृत्व को बांग्लादेश की हिंसा का पैगाम समझ कर आगामी नीति पर विचार करना चाहिए।

होना तख्ता पलट मुझ बाप का

असल में जो अपने को गलतफहमी में सबका बाप समझता इतराता रहता है, अंततः उसका यही हर्ष होता है या कि ऐसा कहें बापों के ही तख्ते पलट होते हैं। वोट के बदले फ्री की रोटी तोडने वालों के क्या तख्ते पलट होंगे? इसलिए जो अपना तख्ता पलट होने से डरते हों, प्लीज वे सब कुछ बनें, पर कभी बाप न बनें। तो लीजिए साहब! मुझे पता भी नहीं चला और कल मेरा भी तख्ता पलट हो गया। ऐसा नहीं कि मैंने बाप होने के बाद किसी के लिए कुछ नहीं किया, पर उसे मेरा बाप धर्म कह किनारे कर दिया गया। जितना मुझसे हो सकता था, बाप होने के नाते सब किया। इधर उधर झूठ कहा, किसके लिए? झूठा बाप बने रहने के लिए। ऑफिस में सिर नीचा किए सौ सौ लिए हाथ फैलाए, किसके लिए? झूठा बाप बने रहने के लिए। ऑफिस में लंच में खाने को सूखी चपातियां ले गया, किसके लिए? झूठा बाप बने रहने के लिए। तख्ता पलट होने से पहले उनकी तरह मुझे भी कतई खबर नहीं हुई कि उनकी तरह मेरा भी भीतर ही भीतर तख्ता पलटने की योजना पर काम हो रहा है। कि मेरे हर घर के हर कल्याणकारी काम में सबको मेरी तानाशाही बदबू नहीं बदबू आ रही है। तख्ते हर किस्म के बापों के पलटते रहे हैं। मसलन, राजनीतिक बापों के तख्ते पलटते रहे हैं। साहित्यिक बापों के तख्ते पलटते रहे हैं। धार्मिक बापों के तख्ते पलटते रहे हैं। बापों के बापों के तख्ते पलटते रहे हैं। और आगे कहूं तो कुंआरे बापों के भी तख्ते पलटते रहे हैं। ऐसे में घर के बापों के तख्ते पलटना कोई नई बात नहीं। यहां तो कई बार तो बाप का तख्ता पलटे बिना ही घर के बाप तक बदल जाते हैं। ऐसे में शुक्र मनाना चाहिए उस बाप को जिसका केवल तख्ता ही पलट हो। कम से कम उसे तो नहीं पलटा गया। किसी का तख्ता पलटने वाले बाहर के दुर्जन नहीं होते, घर के ही सज्जन होते हैं। किसी की नाक काटने को बाजार वालों के पास उतनी पैनी चाकू छुरी नहीं होते जितने अपने ही घर के सदस्यों के पास होते हैं। बाजार वालों को किसी की नाक की हड्डी की मजबूती का पता नहीं होता, अपनों को ही अपनों की नाक की हड्डी की मजबूती का सीक्रेट होता है।

उनका तख्ता पलट हुआ तो उन्हें देश से निकलने के लिए जिस तरह पचास मिनट दिए गए, उसी तरह मेरा तख्ता पलट होने पर मुझे भी कायदे से मेरा सम्मान बरकरार रखते हुए पचास मिनट दिए गए, ताकि मेरा कद भी उनके कद जितना ही रहे। मेरा तख्ता पलटते ही श्रीमती का आदेश हुआ कि मैं जैसे भी हो, मैं उनकी तर्ज पर पचास मिनट में इस घर को छोड़ जाऊं तो तख्ता पलटे ने दोनों हाथ जोड़े कहा, 'वे देश की मुखिया थीं। इसलिए उनको तत्काल हैलिकॉप्टर मिल गया देश से बाहर जाने को, पर मेरे पास तो किसी ऑटो वाले का नंबर भी नहीं। ऐसे में?' 'देखो! मुझे तुमसे अटैचमेंट है, बस, इसीलिए कह रही हूं। वर्ना यहां अब और रुके तो'। घर की सारी हवा बिल्कुल तुम्हारे खिलाफ है। तुम अब इस घर के लिए विकास का नहीं, विनाश का कारण बन चुके हो। किसी को मनमानी नहीं करने देते। सबकी हां में अपनी न अड़ाते हो', चालीस साल से वेतन का पूरा हिसाब लेने वाली धर्मपत्नी ने मुझसे सहानुभूति जताते कहा तो मैंने एक बार फिर सबको संभालने के इरादे से कहा, 'वह तो उसी दिन से मेरे पक्ष में नहीं थी जिस दिन से मैंने इस घर के मुखिया का गधभार अपनी मर्जी से अपनी पीठ पर लिया था। प्लीज! मुझे थोड़ा वक्त तो दो! मैंने अपने जीवन का पल पल और लोन, वेतन का धेला धेला इस घर के लिए दिया है। जब बीड़ी पीने को मन किया तो भी दूसरे बीड़ी पीते की बीड़ी का धुआं ही पिया है। सच कहूं तो एक तथाकथित बाप होने के नाते मैं अपने लिए जिया ही कहां? कभी इसके लिए जिया तो कभी उसके लिए। तुम मेरे साथ नहीं चलोगी?' 'नहीं!' 'पर तुम्हारा मेरा तो जन्म जन्म का रिश्ता है?' 'सत्तात्मक लालसाओं की भूख में कोई रिश्ता रिश्ता नहीं होता। वहां सारे रिश्ते गौण हो जाते हैं। अब रही बात इस घर के दिन-रात जीने की तो कौनसा नया काम किया तुमने? वह तो हर बाप का धर्म होता है।' धर्म पत्नी ने हर बार की तरह अकाट्य तर्क दे मेरे तख्ता पलट को समर्थन दिया। हे हर किस्म के सैद्धांतिक, व्यावहारिक बापो! आपके पास किसी ऑटो वाले का नंबर हो तो यथा शीघ्र भेजें प्लीज! एक डर चुके बाप की जिंदगी का सवाल है।

बैंक नहीं, आप तय करें कि कितना मिलना चाहिए आपको होम लोन! बस अपनाने होंगे ये तरीके

परिवहन विशेष न्यूज

होम लोन (Home Loan) के जरिये आप अपने खुद के घर के सपने को साकार कर सकते हैं। हालांकि बैंक द्वारा ही होम लोन की राशि तय की जाती है। ऐसे में अगर आप लोन की राशि तय करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ तरीके अपनाने होंगे। आइए हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आप कैसे अधिक राशि का लोन ले सकते हैं।

नई दिल्ली। हर कोई चाहता है कि उसके पास अपना खुद का घर हो। लेकिन इस महंगाई में खुद का घर खरीदना एक सपना सा लगता है। इस सपने को साकार करने में होम लोन (Home Loan) काफी मदद करता है। होम लोन के बढ़ते ब्याज दर (Interest Rate) को देखते हुए हम कई झिझक जाते हैं।

अगर आप ज्यादा राशि का लोन लेना चाहते हैं तो आप कुछ तरीके अपना सकते हैं जिसकी मदद से आप अधिक राशि का लोन ले सकते हैं।

अपने क्रेडिट स्कोर पर ध्यान दें

सबसे पहले आपको अपना क्रेडिट स्कोर (Credit Score) चेक कर लेना चाहिए। अगर किसी लोन की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर कम हो रहा है, तो उस पर ध्यान दें। आपको अपने क्रेडिट स्कोर को 750 के पार पहुंचान हैं, ताकि आपको लोन मिलने की संभावना बढ़ जाए।

अगर पहले से आपका कोई लोन चल रहा है तो उसे चुकाकर डेब्ट-टू-इंकम रेश्यो (Debt-To-Income-Ratio) कम करें। यह रेश्यो तय करता है कि आपकी मासिक आय, मौजूदा लोन को चुकाने के लिए सही अनुपात में है। डेब्ट-टू-इंकम रेश्यो कम होने से आपको नया लोन उचित ब्याज दर पर मिल जाएगा।

अपने फाइनेंस की जांच कर लें

आप लोन की राशि चुकाने के लिए कितने तैयार हैं? क्या आपके पास ज्यादा डाउन पेमेंट देने के लिए पर्याप्त राशि है? लोन के लिए आवेदन करने से पहले आपको इन सवालों का जवाब ढूंढ लेना चाहिए। आप यह जरूर देखें कि आपके पास सम्पत्ति की कीमत की 20 फीसदी या अधिक राशि डाउन पेमेंट के लिए हो। इससे आपका लोन का बोझ कम हो जाएगा और आपको उचित ब्याज दर पर लोन की राशि मिल जाएगी।

'बहुत से लोगों के पास डाउन पेमेंट देने के लिए पर्याप्त बचत नहीं होती। इसलिए होम लोन के लिए आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में बचत की राशि हो। या फिर आप चाहें तो अपने लोन के आवेदन को मजबूत बनाने के लिए अपने एमरजेन्सी फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं।'

लोन के विभिन्न विकल्पों पर विचार करें

आप पहले लोन ऑफर को ही फाइनल नहीं करना चाहिए। आप अलग बैंकों, मोर्टगेज संस्थानों और क्रेडिट युनियन्स को में जाकर चेक करें कि कहां आपको कम ब्याज दर पर लोन मिल रहा है। आपको ब्याज दर, लोन की अवधि और शुल्क आदि सभी का कोटेशन लेना चाहिए और उसके बाद ही कुछ फाइनल करना चाहिए।

लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

- नौकरी के वैरिफिकेशन के लिए सैलेरी स्लिप (Salary Slip)
- पिछले दो-तीन सालों की इनकम टैक्स रिटर्न (ITR)
- बैंक स्टेटमेन्ट (Bank Statement)

इन डॉक्यूमेंट्स से आपकी नियमित आय और आर्थिक स्थिरता का पता चल जाता है। इसके अलावा निवास का प्रमाण भी देना होगा।

डाउन चल रही है आईआरडीएआई की साइट, यूजर्स को एक्सेस करने में हो रही परेशानी

IRDAI की वेबसाइट आज यानी 21 अगस्त को डाउन चल रही है और यूजर्स को इसे एक्सेस करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बीमा कंपनियों के अपने कस्टमर्स के KYC डिटेल को रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (CKYCRR) वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद ये समस्या हुई। अब देखना है कि ये कब साइट कब तक फिर से काम करना शुरू करती है।

नई दिल्ली। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के यूजर को एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। IRDA की वेबसाइट 21 अगस्त को बंद हो गई, जिसके कारण कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ये समस्या 20 अगस्त के बाद हुई जब बीमा कंपनियों को अपने पॉलिसीधारकों के वेरिफाइड नो योर कस्टमर (KYC) डिटेल को सेंट्रल KYC रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (CKYCRR) वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए।

बता दें कि CKYCRR एक सेंट्रलाइज्ड KYC सिस्टम के रूप मे काम करता है, जो बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बीमा और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) जैसे ट्रांजेक्शन पर लागू होता है।

पारदर्शिता के लिए खास कदम

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा एजेंट और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के लिए कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को कारगर बनाने के लिए CKYCRR के उपयोग को जरूरी कर दिया है।
- यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और कई क्षेत्रों में वित्तीय लेनदेन की सुरक्षित करने में काम आएगा।
- इससे उन्हें एक-दूसरे के CKYC डेटा तक पहुंचने और उसका उपयोग करने की अनुमति मिलती है, जिससे ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया तेज़ और अधिक कुशल हो जाती है।

1 अगस्त, 2024 से प्रभावी है निर्देश

- इसके साथ ही 31 जनवरी, 2025 तक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों (KRA) को पूंजी बाजार निवेशकों की केवाईसी जानकारी CKYCRR पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।
- ये निर्देश 1 अगस्त, 2024 से प्रभावी है, जो अलग-अलग वित्तीय क्षेत्रों में केवाईसी डेटा को इंट्रीग्रेट करने के IRDAI के प्रयासों के अनुरूप है।

बीमा कंपनियों को भी सीकेवाईसीआरआर से नई जानकारी मिलने पर अपने केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करना होगा।

सोने के दाम स्थिर और चांदी हुई सस्ती, देखिए आज के प्राइस

परिवहन विशेष न्यूज

मंगलवार को पिछले सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला गोल्ड 1400 रुपये उछलकर 74150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि चांदी की कीमत में 150 रुपये की गिरावट हुई है। वैश्विक बाजार में कॉमेक्स सोना 6.10 डॉलर प्रति औंस की गिरावट के साथ 2544.50 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। कॉमेक्स चांदी भी 0.24 प्रतिशत बढ़कर 30.03 डॉलर प्रति औंस पर बोली जा रही थी।

नई दिल्ली। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 74,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही। हालांकि, चांदी की कीमत 150 रुपये की गिरावट के साथ 87,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई।

घरेलू बाजार की स्थिति

मंगलवार को पिछले सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला गोल्ड 1,400 रुपये उछलकर 74,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि, चांदी की कीमत में 150 रुपये की गिरावट हुई है। ये अब 87,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। वहीं, पिछले बंद का भाव 87,150 रुपये प्रति किलोग्राम था। इस बीच, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 73,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा।

ग्लोबल मार्केट का हाल

वैश्विक बाजार में कॉमेक्स सोना 6.10 डॉलर प्रति औंस की गिरावट के साथ 2,544.50 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। शेयरखान बाय बीएनपी पारिबा के शोध विश्लेषक मोहम्मद इमरान ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के बीच मंगलवार को नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद सोना अभी भी 2,500 डॉलर से ऊपर कारोबार कर रहा है।

अमेरिकी डॉलर सूचकांक में कमजोरी और चीन की मजबूत मांग के बीच वैश्विक व्यापारी और उपभोक्ता कीमती धातु पर दांव लगाना जारी रखे हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स चांदी भी 0.24 प्रतिशत बढ़कर 30.03 डॉलर प्रति औंस पर बोली जा रही थी।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक, कमोडिटीज सौमिल गांधी ने कहा कि व्यापारी अब बुधवार को होने वाली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) की नवीनतम बैठक के मिनटों का इंतजार कर रहे हैं, जो फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति दिशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के ईबीजी, कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के उपाध्यक्ष प्रणव मेर के अनुसार, ब्याज दरों में कटौती की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए जैक्सन होल सिंपोसियम (संगोष्ठी) में अमेरिकी फेड चेयर जेरोम पॉवेल के भाषण पर ध्यान केंद्रित है।

भारत में ऑनलाइन विक्रेताओं ने 1.58 करोड़ नौकरियों का किया सृजन

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली स्थित नीति अनुसंधान संस्थान पहले इंडिया फाउंडेशन (पीआइएफ) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार ई-कामर्स भारत में रोजगार देने वाला एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। औसतन ऑनलाइन विक्रेता ऑफलाइन विक्रेताओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक लोगों को रोजगार देते हैं और महिला कर्मचारियों की संख्या करीब दोगुनी है। खुदरा क्षेत्र में ई-कॉमर्स पहुंच के दो सबसे बड़े योगदान रोजगार में वृद्धि और उपभोक्ता कल्याण में सुधार है।

दिल्ली। ऑनलाइन विक्रेताओं ने भारत में 1.58 करोड़ नौकरियों का सृजन किया है। इनमें से 35 लाख नौकरियां महिलाओं को मिली हैं। करीब 17.6 लाख खुदरा उद्यम ई-कामर्स गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक कार्यक्रम में 'भारत में रोजगार तथा उपभोक्ता कल्याण पर ई-कामर्स के शुद्ध प्रभाव का आकलन' नामक रिपोर्ट बुधवार को जारी की।

ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन में ज्यादा महिला कर्मचारी

दिल्ली स्थित नीति अनुसंधान संस्थान 'पहले इंडिया फाउंडेशन' (पीआइएफ) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, ई-कामर्स भारत में रोजगार देने वाला एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। औसतन, ऑनलाइन विक्रेता ऑफलाइन विक्रेताओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक लोगों को रोजगार देते हैं और महिला कर्मचारियों की संख्या करीब दोगुनी है।

ऑनलाइन शॉपिंग में बढ़ी छोटे शहरों की रुचि

रिपोर्ट में कहा गया, खुदरा क्षेत्र में ई-कॉमर्स पहुंच के दो सबसे बड़े योगदान रोजगार में वृद्धि और उपभोक्ता कल्याण में सुधार है। भौतिक बाजारों को विस्थापित करने के बजाय, ई-कामर्स छोटे शहरों जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया, 'हमारे आंकड़ों से पता चलता है कि बड़े शहरों के उपभोक्ताओं की तुलना में छोटे शहरों के ज्यादा उपभोक्ता ऑनलाइन शापिंग पर प्रतिमाह 5,000 रुपये से अधिक खर्च करते हैं।'

रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक ई-कॉमर्स विक्रेता औसतन करीब नौ लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से दो महिलाएं हैं। वहीं प्रत्येक ऑफलाइन विक्रेता करीब छह लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से केवल एक महिला है। कार्यक्रम में मौजूद नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि ई-कामर्स ने भारत के खुदरा परिदृश्य में क्रांति ला दी है।

2047 तक 55 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है अर्थव्यवस्था का आकार: कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन

दुनिया के प्रमुख अर्थशास्त्री ने कहा कि विकसित अर्थव्यवस्थों में निवेश अपने चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि देश के आठ प्रतिशत की दर से बढ़ने का दूसरा कारण आने वाले समय में ऐसे क्षेत्रों का दोहन किया जाना है जिन क्षेत्रों में आज तक काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उद्यमिता नवाचार और निजी ऋण सृजन अन्य तीन प्रमुख स्तंभ हैं।

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने बुधवार को कहा कि अगर डॉलर के लिहाज से विकास दर 12 प्रतिशत बनी रहती है तो 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 55 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।

2018 से 2021 तक सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे सुब्रमण्यन ने कोलकाता में उद्योग संगठन सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा कि 2016 से मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अंदर रखने के प्रयास ने इसे औसत पांच प्रतिशत पर लाने में मदद की है।

...तो हर छह साल में दोगुनी हो जाएगी अर्थव्यवस्था

उन्होंने कहा कि 2016 से पहले मुद्रास्फीति की औसत दर 7.5 प्रतिशत थी। सुब्रमण्यन ने कहा कि आठ प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि और पांच प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर को मिला लें तो नॉमिनल विकास दर 13 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा के मूल्यह्रास की दर अगर एक प्रतिशत भी रहती है तो डॉलर के लिहाज से भारत की वास्तविक वृद्धि दर 12 प्रतिशत होगी। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का आकार हर छह साल में दोगुना हो जाएगा।

आठ प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करना संभव

उन्होंने कहा, "वर्तमान में अर्थव्यवस्था का आकार 3.8 ट्रिलियन डॉलर है और 2047 में इसका संभावित आकार 55 ट्रिलियन डॉलर को छू सकता है।" सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत के लिए वास्तविक रूप से आठ प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करना संभव है।

दुनिया के प्रमुख अर्थशास्त्री ने कहा कि विकसित अर्थव्यवस्थों में निवेश अपने चरम पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि देश के आठ प्रतिशत की दर से बढ़ने का दूसरा कारण आने वाले समय में ऐसे क्षेत्रों का दोहन किया जाना है, जिन क्षेत्रों में आज तक काम नहीं हुआ है। ऐसा करने से उत्पादकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि उद्यमिता, नवाचार और निजी ऋण सृजन अन्य तीन प्रमुख स्तंभ हैं जो अर्थव्यवस्था को वास्तविक रूप से आठ प्रतिशत की दर से बढ़ने में मदद करेंगे।

स्टारबक्स अपने नए सीईओ को दे रही कॉर्पोरेट जेट की सुविधा, घर से 1600 किमी दूर है ऑफिस

स्टारबक्स न्यू सीईओ स्टारबक्स (स्टारबक्स) ने नए सीईओ के लिए ब्रायन निकोल (ब्रायन निकोल) की नियुक्ति की है। जहां ब्रायन निकोल की सैलरी मिलियन डॉलर में है तो वहीं उन्हें कॉर्पोरेट जेट की सुविधा भी मिल रही है। दरअसल ब्रायन के घर और ऑफिस की दूरी 1600 किमी है। इस वजह से उन्हें जेट की सुविधा मिल रही है। पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली। स्टारबक्स के नए सीईओ ब्रायन निकोल (ब्रायन निकोल) को कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट जेट की सुविधा दी जा रही थी। दरअसल, ब्रायन के घर और ऑफिस की दूरी 1600 किलोमीटर है। रोजाना इतनी दूरी तय करने के लिए स्टारबक्स अपने सीईओ को यह सुविधा दे रहे हैं।

कंपनी उठाएगी खर्चा

ब्रायन निकोल का घर कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट में है और स्टारबक्स का हेडक्वॉर्टर वॉशिंगटन के शहर सिएटल (Seattle) में है। इन दोनों शहरों का हवाई दूरी लगभग 1600 किमी है। ऐसे में इतनी ज्यादा दूरी को कम समय में कवर करने के लिए कंपनी कॉर्पोरेट जेट की सुविधा दे रही है। इस सुविधा का पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी।

कंपनी ने बताया कि जब ब्रायन निकोलको कहीं काम के लिए नहीं जाना होगा, तब उन्हें ऑफिस आना होगा। कंपनी के हाइब्रिड पॉलिसी के मुताबिक ब्रायन निकोलको अगर वह ऑफिस के काम से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हफ्ते में कम से कम तीन दिन ऑफिस आना होगा।

आपको बता दें कि सीईओ का पदभार संभालने के बाद से अभी तक ब्रायन ने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है। वह अगले महीने से सीईओ की जिम्मेदारी संभालेंगे।

ब्रायन निकोलको की सैलरी

स्टारबक्स के नए सीईओ ब्रायन निकोलको की सैलरी लगभग 113 मिलियन डॉलर (9,48,61,57,900 रुपये) होगी। इसमें उनकी बेसिक सैलरी 1.6 मिलियन डॉलर (13.42 करोड़ रुपये) है। काम के आधार पर उन्हें बोनस के तौर पर सालाना 3.6 मिलियन डॉलर से 7.2 मिलियन डॉलर मिलेगा। इसके अलावा इन्हें कंपनी के शेयर में हिस्सेदारी भी मिलेगी।

स्टारबक्स के पूर्व सीईओ

ब्रायन निकोलको से पहले स्टारबक्स के पूर्व सीईओ भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन थे। माना जा रहा है कि कंपनी के खराब प्रदर्शन की वजह से नरसिम्हन को पद से हटाया गया था। पिछले साल ही लक्ष्मण नरसिम्हन ने स्टारबक्स सीईओ का पद संभाला था।

अब रेल हादसों से मिलेगी निजात

रेलगाड़ियों को मिला 'कवच' सुरक्षा

भारत में हर साल कई रेल दुर्घटनाएं होती हैं। जिनमें कई बार बड़े पैमाने पर जान-माल की हानि होती है। अब इन हादसों को रोकने के लिए इंजनों में सुरक्षा कवच लगाया जा रहा है। अभी तक 65 इंजनों में इसे लगाया जा चुका है। 150 में अभी लगाया जाना है। देश में इस समय 20 हजार रेलवे इंजन हैं। अगले दो सालों में इन सभी में इसे लगाया जाएगा।

नई दिल्ली। लोको पायलट की गलती या तकनीकी त्रुटि से एक ही पटरी पर दो ट्रेनों के आने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे इंजनों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। दिल्ली मंडल इस वर्ष अपने 150 इंजनों को सुरक्षा कवच से सुसज्जित कर देगा।

पहले चरण में यात्री ट्रेन (Train News) वाले इंजन में इसे लगाया जा रहा है। उसके बाद मालगाड़ी के इंजन में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसी माह रेल मंत्री ने कहा था कि भारतीय रेलवे को टक्कर रोधी स्वदेशी उपकरण कवच 4.0 से युक्त करने का काम तेजी से चल रहा है।

देश में इस समय करीब 20 हजार रेलवे इंजन

देश में इस समय लगभग 20 हजार रेलवे इंजन हैं। दो वर्षों में इन सभी इंजनों में कवच लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दो वर्षों में लगभग नौ हजार किलोमीटर ट्रैक पर भी कवच उपकरण लगाने का लक्ष्य है। दिल्ली मंडल के अधिकारियों ने बताया कि गाजियाबाद इलेक्ट्रिक लोको शेड में यह काम चल रहा है।

अभी तक 65 इंजनों में लगासुरक्षा कवच

यहां अब तक 65 इंजनों में सुरक्षा कवच लगा दिया गया है। इस वित्त वर्ष में 85 और इंजनों में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यदि लोको पायलट किसी कारण से ब्रेक लगाने में विफल रहता है तो कवच उपकरण से ट्रेन की गति को धीमी करने और स्वचालित ब्रेक लगाने में मदद मिलेगी। इससे खराब मौसम में भी सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित हो सकेगा। लेवल क्रॉसिंग के पास ट्रेन के पहुंचने से स्वचालित हार्न बजने, नियंत्रण कक्ष से निगरानी सहित कई सुविधाएं हैं, जिससे दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

अब ड्यूटी पर भूखे नहीं खड़े रहेंगे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, एक कॉल में पहुंचेगा फूड ट्रक; मिलेगा गरमा-गरम

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों को अब गरमा गरम ताजा खाना मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस ने अपने एक लाख से अधिक कर्मियों को ताजा भोजन उपलब्ध कराने को लेकर योजना बनाई है।

इसके लिए फूड ट्रक दिल्ली की सड़कों पर इन पुलिसकर्मियों को खाना उपलब्ध कराने के लिए उतारा जाएगा और इसे धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा। अकसर देखने को मिलता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपने व्यस्त शेड्यूल के कारण भूखे रह जाते हैं और गर्मी व बरसात के मौसम में उन्हें परेशानी होती थी। ऐसे में फूड ट्रक से उन्हें भूखे रहने की समस्या से थोड़ी राहत मिलेगी।

दिल्ली पुलिस पहले से ही पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली के कुछ इलाकों में मोबाइल कैंटीन वैन चला रही है। दिसंबर 2019 में पूर्व पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने रिजर्व स्टाफ के लिए कैंटीन वैन नाम की प्रोजेक्ट के तहत इस वैन को शुरू किया था। ऐसे में बिजी शेड्यूल और कठिन परिस्थितियों की वजह से कई बार इन लोगों को खाने की फुर्सत भी नहीं मिलती है।

कॉल करके मंगवा सकेंगे फूड ट्रक

दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि बहुत ज्यादा गर्मी या मानसून के दौरान ट्रैफिककर्मियों के लिए चलते-फिरते भोजन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने पोर्टेबल फूड सर्विस शुरू की है। उन्होंने बताया कि मेन्यू में दाल, एक सब्जी, दो चपाती और चावल वाली शाकाहारी थाली होगी। मेन्यू अलग-अलग होगा।

फूड ट्रक की देख रेख एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी, एक कांस्टेबल, एक सब-इंस्पेक्टर और एक ड्राइवर द्वारा की जाएगी। माना जा रहा है कि कुछ हफ्तों में यह ट्रक रोड पर दिखने लगेगा। अगर किसी खास ट्रैफिक सर्किल में लंच या डिनर की जरूरत होती है, तो वे वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए प्रभारी इंस्पेक्टर को कॉल कर सकते हैं।

ट्रेन पर रोक, इंटरनेट बंद... भारत बंद का बिहार-झारखंड समेत पूरे देश में कैसा रहा असर?

आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति (आरबीएसएस) ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त 2024 को भारत बंद की घोषणा की। हालांकि बुधवार को आयोजित विपक्षी दलों का भारत बंद का बिहार और झारखंड तक सीमित रहा। पंजाब में बाजार खुले तो हरियाणा उत्तराखंड व दिल्ली-एनसीआर में सबकुछ सामान्य रहा।

नई दिल्ली। एससी-एसटी आरक्षण में उप-वर्गीकरण व क्रीमीलेयर निर्धारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को आयोजित विपक्षी दलों का भारत बंद का बिहार और झारखंड तक सीमित रहा। आदिवासी इलाकों में भी जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व ओडिशा समेत ज्यादातर राज्यों में कोई खास असर नहीं दिखा।

पंजाब-हरियाणा में क्या रहा हाल?

पंजाब में बाजार खुले तो हरियाणा, उत्तराखंड व दिल्ली-एनसीआर में सबकुछ सामान्य रहा। इंडी गठबंधन के साथ-साथ अन्य गैर-भाजपा संगठनों ने बंद का समर्थन किया था।बिहार में एहतियातन निजी स्कूलों को बंद रखा गया था। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आवागमन बाधित किया। सड़क पर टायर जलाकर आगजनी की। दुकानें बंद कराई गईं।

पटना में पुलिस की लाठीचार्ज

पटना के डाकबंगला चौराहे पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस क्रम में सिपाही ने गलती से सदर एसडीओ श्रीकांत कुण्डलिक खांडेकर पर ही लाठी चला ला दी। एसडीओ ने इसे मानवीय भूल बताया। शेखपुरा जिले में बंद समर्थकों ने पुलिस की पिटाई कर दी। इसमें एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर बिहार में सप्तक्रांति एक्सप्रेस समेत चार ट्रेनें रोकी गईं।

बेगूसराय में तिनसुकिया अमृतसर एक्सप्रेस रोकी गई। आरा स्टेशन पर रानी कमलापति एक्सप्रेस को रोककर प्रदर्शन किया गया। पूर्वी चंपारण में आधा दर्जन बंद समर्थकों को हिरासत में लिया गया। बांका में प्रदर्शनकारियों के पथराव में थानाध्यक्ष सहित पांच पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। छह लोगों को हिरासत में लिया गया है। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पटना और अन्य इलाकों में प्रदर्शनों का नेतृत्व किया।

झारखंड में सत्तारूढ़ दलों का हंगामा

झारखंड में सत्तारूढ़ दलों व वामपंथी दलों के समर्थन के कारण बंद का असर दिखा। सार्वजनिक बसें सड़कों से नदारद रहीं और स्कूल बंद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू का अपना दौरा रद कर दिया। रांची विश्वविद्यालय में बीएड के छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा स्थगित कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने रांची में कई जगहों पर टायर जलाए और नाकेबंदी की।

बंद समर्थकों ने पलामू, गोड्डा, दुमका, गढ़वा और अन्य जिलों में सड़क जाम किया गया। ओडिशा में रेल और सड़क यातायात आंशिक रूप से प्रभावित रहा, लेकिन सरकारी कार्यालय, बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और शैक्षणिक संस्थान सामान्य रूप से काम करते रहे।

भुवनेश्वर व संबलपुर में रोकी गई ट्रेनें

भुवनेश्वर व संबलपुर में कुछ समय के लिए ट्रेनें रोकी गईं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रदर्शनकारियों ने खुली दुकानों को बंद कराने के लिए हंगामा किया, तोड़फोड़ की कोशिश। ग्वालियर में पहले से ही स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया था। उज्जैन में व्यापारियों और बंद समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की हुई। छत्तीसगढ़ में रायपुर समेत औद्योगिक अंचलों में काम-काज सामान्य रहा। आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में इसका असर देखा गया। शैक्षणिक संस्थान, दुकान-बाजार बंद रहे।

राजस्थान में जयपुर सहित अधिकतर जिलों में छोटी-मोटी घटनाओं को छोड़कर बंद शांतिपूर्ण रहा। उत्तर प्रदेश में बाजार खुले रहे, कुछ जगह जाम लगाने का प्रयास हुआ तो छिटपुट झड़पें भी हुईं, लेकिन ज्यादातर जिलों में बंद समर्थकों ने विरोध-प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बंद का समर्थन करने वाली सपा, बसपा और आजाद समाज पार्टी की प्रदर्शन में भागीदारी सांकेतिक ही रही। अलीगढ़ में लाठी-डंडे लिए बंद समर्थकों ने जंक्शन स्टेशन पर जाने का प्रयास किया। जीआरपी और आरएएफ के जवानों ने रोका तो कहासुनी हुई।

बलिया के नगरा में जुलूस

बलिया के नगरा में जुलूस निकालने वालों ने कुछ दुकानों में तोड़फोड़ भी की। उत्तराखंड में कोई असर नहीं दिखा। देहरादून समेत कुछ शहरों में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। पंजाब में कुछ जगहों पर बसपा ने प्रदर्शन किया।

हरियाणा में दलित संगठन प्रदर्शन तक सीमित रहे। हड़ताल का गुजरात के आदिवासी इलाकों में भी कुछ असर दिखा, जिसमें छोटा उदयपुर, नर्मदा, सुरेंद्रनगर, साबरकांठा और अरावली जिले शामिल हैं। इन इलाकों में बाजार बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने सुरेन्द्रनगर जिले के वधावन तालुका में एक मालगाड़ी को कुछ देर के लिए रोका और नारे लगाए। सूरत जिले के उमरपाड़ा कस्बे में दोपहर में दुकानें बंद रहने के कारण सन्नाटा पसरा रहा।

डॉक्टर्स हड़ताल : 'काम पर वापस लौट आइए, मरीज हो रहे परेशान...'

परिवहन विशेष न्यूज

कोलकाता में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले को लेकर दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल बुधवार को भी जारी है। इससे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए एम्स ने डॉक्टरों से ड्यूटी पर वापस लौटने की अपील की है।

नई दिल्ली। एम्स प्रशासन ने रेजिडेंट डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है। एम्स के स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए डीन (अकादमी) की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या के विरोध में एम्स सहित दिल्ली के सभी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं।

सरकार से अध्यादेश लाने की मांग

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित करने के आदेश के बाद भी रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल समाप्त नहीं की। ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (एफएआइएमए) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाने की मांग को लेकर वह हड़ताल जारी रखने की घोषणा की है। उन्होंने इसे लेकर सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की है।

काम पर लौटें डॉक्टर

एम्स प्रशासन बुधवार को पत्र जारी कर कहा, ₹एम्स परिवार देशभर के सभी स्वास्थ्य पेशवरों की सुरक्षा का पक्षधर है। वह उनके साथ खड़ा है। डॉक्टर के तौर पर उनका कर्तव्य है कि कोई भी मरीज बिना उपचार के वापस नहीं लौटे। भारत सरकार भी स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर सकारात्मक निर्देश दिया है। इसे ध्यान में रखकर सभी रेजिडेंट डॉक्टरों को काम पर लौटना चाहिए, जिससे कि मरीजों की परेशानी दूर हो सके।"

साथ ही डॉक्टरों व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के तत्कालीन चिंता के समाधान के लिए एक कमेटी गठित की है। डीन (अकादमी) की अगुवाई वाली समिति में डीन (अनुसंधान), डीन (परीक्षा), चिकित्सा अधीक्षक (एच) और मुख्य सुरक्षा अधिकारी इसके सदस्य हैं। इससे पहले एम्स प्रशासन ने आंतरिक सुरक्षा ऑडिट करने का निर्णय लिया है।

डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, मरीजों और उनके तीमारदारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बायोफिजिक्स की प्रोफेसर पुनीत कौर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

इसमें प्रोफेसर प्रताप शरण (मनोचिकित्सा विभाग), प्रोफेसर संजय राय (अधीक्षक छात्रावास), प्रोफेसर सुषमा सागर (ट्रामा सर्जरी विभाग), प्रोफेसर गिरिराज रथ (रजिस्ट्रार), कर्नल दिग्विजय सिंह (मुख्य सुरक्षा अधिकारी), दीपक भुटाले (अधीक्षण अभियंता) इसके सदस्य हैं। समिति में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है।

इस वजह से बुधवार को भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। फेडरेशन आफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (एफएआइएमए) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन ड्यूटी पर वापस लौटने की अपील को मानने से इनकार कर दिया। एसोसिएशन का कहना है कि उनकी मांग डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अलग कानून बनाने व अध्यादेश लाने की है। अभी यह मांग पूरी नहीं हुई है।

सरकारी अस्पतालों में नहीं सुधरे हालात

कोलकाता में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और फिर हत्या के मामले के बाद भी सरकारी अस्पतालों में हालात सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार रात एलएन और जीबी पंत अस्पताल में पड़ताल की गई, तो देखा गया कि रात में महिला डॉक्टर इमरजेंसी में अपनी सेवाएं दे रही थीं। सुरक्षा में तैनात कर्मी बस नाम के लिए बैठे थे। लोग बिना रोकटोक और बिना जांच के अस्पताल में दाखिल हो रहे थे।

रात में महिला चिकित्सक दे रहीं सेवाएं

एलएन अस्पताल में सोमवार रात करीब नौ बजे तीन दो महिला चिकित्सक और एक नर्स सेवा दे रही थीं। इस दौरान इमरजेंसी में मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। इमरजेंसी के गेट पर दो गार्ड मौजूद थे, जो इक्का-दुक्का मरीजों व उनके परिजनों से पूछताछ के बाद अंदर जाने की इजाजत दे रहे थे।

देशभर में चल रहे हंगामे के बाद भी अस्पताल में रात के समय महिला चिकित्सकों व नर्सों की ड्यूटी लगाई जा रही है। वहीं जीबी पंत अस्पताल की इमरजेंसी में भी रात करीब साढ़े नौ बजे तीन महिला चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रही थीं। यहां गेट पर बैठे सुरक्षाकर्मी अनजान लोगों को अंदर जाने से रोकते दिखाई दिए।

हॉस्टल के गेट पर नहीं दिखे सुरक्षाकर्मी

एलएन अस्पताल के महिला हास्टल में सैकड़ों की संख्या में चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी व नर्स रहती हैं। सोमवार देर शाम इस हॉस्टल के गेट पर कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था। जबकि यहां सबसे अधिक कड़ी सुरक्षा की आवश्यकता रहती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाही से कोई बड़ा हादसा फिर से घटित हो सकता है।

भारत बंद का समर्थन किया पूर्वी दिल्ली मे वकार चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ

सुषमा रानी, एससी एसटी के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की क्रीमी लेयर वाले फैसले के खिलाफ दलित संगठनों ने बुधवार को भारत बदं का आवाहन किया था। जिसके चलते कहीं बंद रहा कहीं नहीं रहा पूर्वी दिल्ली में भी आरक्षण के समर्थन मे कोलेजियम सिस्टम के विरोध मे आज पूरी दिल्ली समेत लक्ष्मी नगर में बसपा नेता वकार चौधरी के नेतृत्व में बसपा कार्यकर्तों ने प्रदर्शन किया और माननीय राष्ट्रपति को ज़िला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया

पूर्वी दिल्ली के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी वकार चौधरी ने कहा कि आज पूरे देश में बहन मायावती के आह्वान पर बंद किया गया और प्रदर्शन किया , उन्होंने आगे कहाँ की आज केंद्र सरकार साज़िश करकर जिस तरह आरक्षण के समर्थन मे कोलेजियम सिस्टम ला रही है , और आरक्षण ख़त्म करना चाहती है उसे किसी भी क़ीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस मोका पर बसपा के सेकड़ो कार्यकर्तों ने हिस्सा लिया जिस में मुख्य रूप से लक्ष्मी नागफ़ ज़िला अध्यक्ष अमर सिंह सुजीत सम्राट सलीम ख़ान, दर्शन लाल, सुनील कुमार ,गांधी गोतम आदि मुखरूप से मोजूद रहे।

ओड़िशा के एक राज्यसभा आसन के लिए दो बीजेपी नेता अपना नामांकन पत्र दाखिल किया , बीजेपी मे क्या चल रहा है

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड उडीशा

भुबनेस्वर : सुबह-सुबह बीजेपी नेता ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया । दोपहर में एक और नेता ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया । जिसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है । हाल ही में बीजेडी छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं ममता महंत ने बुधवार सुबह राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।ममता ने विधानसभा आकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना नामांकन दाखिल किया । वहीं इसके कुछ ही घंटों बाद एक और बीजेपी नेता ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया ।

बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान ने स्वतंत्र रूप से नामांकन पत्र दाखिल किया है । भुवनेश्वर से बीजेपी विधायक उम्मीदवार जगन्नाथ प्रधान ने राज्यसभा के लिए अपनी उम्मीदवारी विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप दी है । जिसने सभी को हैरान कर दिया । बड़ी बात यह है कि जगन्नाथ प्रधान ने स्वतंत्र रूप से नामांकन भरा है । हालांकि, इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि एक उम्मीदवार के रहते पार्टी के एक नेता ने स्वतंत्र रूप से नामांकन क्यों भरा है । बड़ा सवाल यह है कि आखिर जगन्नाथ प्रधान को अपना नामांकन पत्र क्यों दाखिल करना पड़ा ।

भाजपा प्रत्याशी ममता महंत ने आज सुबह नामांकन पत्र दाखिल किया। ममता ने बुधवार को राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया. आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, बीजेपी की ओर से ममता महंत ने नामांकन दाखिल किया । ममता महंत ने मुख्यमंत्री मोहन माझी, राज्य भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल, मंत्री सुरेश पुजारी और राज्य भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दोपहर बाद जग्गा प्रधान ने 10 भाजपा विधायक उम्मीदवारों के साथ स्वतंत्र रूप से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया ।बीजेपी ने कल यानी मंगलवार को ममता को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023